Website: www.winews.in | Email: winews.in@gmail.com | दिल्ली, नोएडा, हापुड़, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रूड़की, हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा,राजस्थान, पंजाब, बहराइच,रामपुर, लखनऊ, काशीपुर, देवबंद में प्रसारित

दैनिक गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

वेलकम इंडिया

RNI NO. UPHIN/2018/76874

नये भारत की नई सोच

वर्ष: 07 अंक: 207 | बुधवार, 05 अगस्त-2026 (गाजियाबाद) | पेज-8 | मूल्य-एक रुपया

आग बुझाते-बुझाते बुझ गई दो जांबाजों की जिंदगी

भरभराकर गिरी दीवार और लोहे की बीम में दबे फायरकर्मी, दो की मौत; तीन गंभीर, दो दमकल गाड़ियां क्षतिग्रस्त

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा। इकोटेक-3 थाना क्षेत्र स्थित ILGIM कंपनी में देर रात लगी भीषण आग ने आग बुझाने पहुंचे अग्निशमनकर्मियों की जिंदगी में मातम भर दिया।

आग पर काबू पाने के दौरान कंपनी की दीवार और लोहे की भारी बीम अचानक भरभराकर गिर गई। इसकी चपेट में आने से कई फायरकर्मी मलबे में दब गए। गंभीर रूप से घायल फायरमैन रोहित और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तीन अन्य अग्निशमनकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। फायर विभाग और एसडीआरएफ की टीमों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। मलबे में फंसे जवानों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में फायर विभाग की दो दमकल गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर, नोएडा ने संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ अस्पताल पहुंचकर घायल अग्निशमनकर्मियों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने चिकित्सकों से घायलों की स्थिति और उपचार की जानकारी ली। पुलिस कमिश्नर ने घायल कर्मियों और उनके परिजनों से बातचीत कर हरसंभव सहायता और बेहतर उपचार का आश्वासन दिया। उन्होंने घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

आग की वजह और सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

भीषण अग्निकांड और उसके बाद हुए हादसे ने कंपनी की अग्निसुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आग किस वजह से लगी और फायरकर्मियों के अभियान के दौरान दीवार व लोहे की बीम अचानक क्यों गिरी, इसकी जांच महत्वपूर्ण है। कंपनी में सुरक्षा मानकों, आग बुझाने की व्यवस्था और अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। आग के पीछे किसी लापरवाही, तकनीकी कारण, साजिश या इंश्योरेंस से जुड़े पहलू की भूमिका थी या नहीं, इसका सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस, फायर विभाग और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। दो जांबाज अग्निशमनकर्मियों की मौत से विभाग में शोक की लहर है।

पीएम के जवाब का इंतजार

सरकार को पिटीशन की कॉपियां सौंप धरने से उठे केजरीवाल

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल धरने से उठ गए हैं और उनके द्वारा लाई गई तकरीबन 2.30 लाख पिटीशन को गाड़ियों में भरकर सरकार को सौंप दिया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि, 'ई20 के खिलाफ 2 लाख 33 हजार से ज्यादा लोगों की साइन की गई पिटीशन की कॉपी अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचा दी गई है। अब देश को प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं को प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने से रोक दिया था। जिसके बाद वे ई20 पेट्रोल के खिलाफ 2.30 लाख से ज्यादा याचिकाएं सौंपने जा रहे थे। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अअढ नेता जैस्मीन शाह और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ फिरोज शाह रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार की ई20 पेट्रोल को बढ़ावा देने की नीति के खिलाफ देश भर से इकट्ठा की गई याचिकाएं सौंपने के लिए हुए इस मार्च में करीब 100 लोग शामिल हुए। कई लोगों का आरोप है कि इथेनॉल-मिश्रित ईंधन का वाहन मालिकों पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि, सरकार इस बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे चुकी है। ढांडा ने कहा, 'लोग बहुत परेशान हैं; वे मुश्किल में हैं। 30 करोड़ वाहन खराब होने की कगार पर हैं और प्रधानमंत्री किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। इथेनॉल को केवल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में थोपा जा रहा है... वहां से बचा हुआ इथेनॉल भारत में खपाया जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिलेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वे युवाओं से भी नहीं मिलेंगे। फिर उन्हें मिलना पड़ा।

2.30 लाख याचिकाओं पर हस्ताक्षर

मार्च से पहले समर्थकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पार्टी देश भर के लोगों द्वारा हस्ताक्षरित 2.30 लाख से अधिक याचिकाएं लेकर जा रही है और सरकार से करोड़ों वाहन मालिकों की चिंताओं को सुनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा हम देश भर के लोगों द्वारा हस्ताक्षरित 2.30 लाख से अधिक याचिकाओं के साथ प्रधानमंत्री के आवास पर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उन करोड़ों वाहन मालिकों की चिंताओं को सुने जो ई20 पेट्रोल के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप नेता अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि इथेनॉल–मिश्रित पेट्रोल के कारण 30 करोड़ वाहन खराब होने की कगार पर हैं।

प्रदर्शनकारियों को फिरोज शाह से आगे जाने की इजाजत नहीं

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को 5, फि रोज शाह रोड से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस के एक सूत्र ने कहा किसी को भी 5, फि रोज शाह रोड से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। हमने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स समेत काफी सुरक्षा बल तैनात किए हैं।

आसाराम को 13 साल बाद पहली बार मिली 20 दिन की पैरोल, हाईकोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को फटकार

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उनकी सजा को राजस्थान हाईकोर्ट ने दो महीने पहले बरकरार रखा था लेकिन सोमवार 03 अगस्त को उनकी 20 दिन की पैरोल की याचिका को मंजूरी दे दी है। इस राहत के चलते आसाराम 13 साल बाद 20 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। दरअसल, हाईकोर्ट ने जोधपुर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा उनकी पैरोल याचिका खारिज करने की भी आलोचना की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की पीठ ने 85 वर्षीय आसाराम को उनकी उम्र और 13 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताने के कारण यह राहत प्रदान की। आसाराम की उम्रकैद की सजा मई में बरकरार रखी गई थी। मई में न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित और न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें सामूहिक बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था। उस समय आसाराम जमानत पर बाहर थे। पीठ ने जमानत रद्द कर दी, जमानत बांड जब्त करने का आदेश दिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा, 'अपीलकर्ता सजा के समय 73 वर्ष का था। अब वह 86 वर्ष का है। वह उम्र के बोझ से दबा हुआ और बीमारियों से ग्रस्त होकर हमारे सामने खड़ा है और अपनी नरमी की अपील पर पुनर्विचार करने की गुहार लगा रहा है। हम उसे कोई रियायत नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी दुर्बलता पीड़ित की आवाज को नजरअंदाज करने का औचित्य नहीं ठहरा सकती। हाईकोर्ट ने कहा, 'इसे नजरअंदाज करना आपराधिक न्याय प्रणाली में समाज के विश्वास को हिला देना होगा और एक गलत संदेश देना होगा जो किसी भी अदालत को कभी नहीं देना चाहिए, खासकर तब जब अपराधी एक स्वयंभू धर्मगुरु के आवरण में छिपा हो।'

याचिकाकर्ता के फरार होने की कही बात

इस मामले में राजस्थान और अन्य पक्षों के वकीलों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 31 जुलाई को जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित बैठक की विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। कार्यवृत्त के अनुसार समिति ने आसाराम की 20 दिन की पैरोल याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पुलिस से सूचना मिली है कि याचिकाकर्ता फरार हो सकता है। इतना ही नहीं, राजस्थान कैदी पैरोल रिहाई नियम, 1958 के नियम 14(क) के तहत उसे पैरोल देने के योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान राज्य के बाहर एक आपराधिक मामला दर्ज है और उसे दूसरे राज्य (गुजरात के गांधीनगर) की अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है।

नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से की मुलाकात

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। चार अगस्त जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हार के एक दिन बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले। प्रधानमंत्री के साथ नीतीश की मुलाकात के दौरान जदयू नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार जी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।' नीतीश ने कहा कि उन्होंने यहां संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यालय में उनसे शिष्टाचार भेंट की। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव इसलिए कराना पड़ा, क्योंकि नितिन नवीन के पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने और फिर राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 मतों के अंतर से हराया। दस बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश ने इस साल अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में पहली बार एक भाजपा नेता (सम्राट चौधरी) ने सरकार की कमान संभाली। बिहार में भाजपा और जदयू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा हैं।

क्राइम कर विदेश भागने वालों पर बड़ा प्रहार: 36 देशों में ऑपरेशन त्रिशूल चलाकर 274 भगोड़ों को भारत लाकर मोदी सरकार ने रचा इतिहास

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सशक्त मार्गदर्शन में भारत ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। वर्ष 2019 से 2026 के बीच दुनिया के 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाकर मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब अपराध करके विदेश भाग जाना सुरक्षित विकल्प नहीं रह गया है।

पहले की सरकारों में राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण प्रत्यर्पण की प्रक्रिया वर्षों तक फाइलों में उलझी रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगोड़ों के प्रत्यर्पण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे 'मिशन मोड' में आगे बढ़ाकर कानून के शिकंजे को वैश्विक स्तर तक मजबूत किया।

आज भारत ने एक ऐसा एकीकृत, खुफिया आधारित और अत्याधुनिक तकनीक से लैस मॉडल विकसित किया है, जिसके माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपराधियों का पता लगाकर उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हुई है। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार की रणनीति तीन मजबूत स्तंभों– वैश्विक अभियान, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति पर आधारित रही है।

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि भगोड़े अपराधियों का मुद्दा केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और न्याय व्यवस्था से जुड़ा विषय है। इसी सोच के अनुरूप केंद्र सरकार ने लगातार कानूनी और संस्थागत सुधार किए हैं।

हम आपको याद दिला दें कि मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में ठकअ संशोधन अधिनियम और वअढअ संशोधन अधिनियम लागू किए, जबकि वर्ष 2024 में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों में पहली बार इठरर की धारा 355 और 356 के माध्यम से 'ट्रायल इन ऐब्सेन्शिया' का प्रावधान किया गया। अब कोई अपराधी विदेश में बैठकर भारतीय कानून का मजाक नहीं उड़ा सकेगा; उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चल सकेगा और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इंटरपोल और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया है। पिछले तीन वर्षों में 401 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए। वर्ष 2025 में लॉन्च किए गए भारतपोल ने 1,400 से अधिक केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर सूचना साझा करने की प्रक्रिया को कई सप्ताह से घटाकर महज 3 से 10 दिन तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा, मोदी सरकार ने आर्थिक अपराधियों के खिलाफ भी अभूतपूर्व कार्रवाई की है। PMLA के सख्त क्रियान्वयन के चलते वर्ष 2019 से 2026 के बीच 17,874 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जबकि 18,762 करोड़ की राशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई। यह उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जो देश का पैसा लूटकर विदेश भाग जाने का सपना देखते हैं। साथ ही विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे अपराधियों को खोजने के लिए 'ऑपरेशन त्रिशूल' चलाया गया, जिसमें सैटेलाइट तकनीक, डिजिटल फुटप्रिंट, जियो-लोकेशन और प्रोफाइल मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। इससे यह साबित हुआ कि आधुनिक भारत की सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच अब सीमाओं से कहीं आगे तक है। इन्हीं सब प्रयासों के चलते वर्ष 2019 से 2026 के बीच भारत 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाने में सफल रहा।

संपादक की कलम से

कांवड़ यात्रा और बेरोजगार युवाओं का मुद्दाः आस्था और अवसर के बीच का अंतर

ललित शर्मा
संपादक

हर साल श्रावण के पवित्र महीने में, उत्तर भारत की सड़कें केसर से भर जाती हैं, क्योंकि लाखों कांवड़िया कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। वे हरिद्वार और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों से पवित्र गंगाजल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह भक्ति, अनुशासन, सहनशीलता और सामूहिक आस्था का एक अद्भुत उदाहरण है। इन तीर्थयात्रियों में युवाओं की संख्या काफी अधिक होती है। उनका उत्साह और शारीरिक शक्ति भारत के युवाओं की अपार ऊर्जा का प्रमाण है। हालांकि, इन युवा तीर्थयात्रियों के साथ एक बड़ा सवाल उठता है : इनमें से कितने लोग साल के बाकी समय में नौकरी की तलाश करते हैं और एक स्थिर भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं? यह धार्मिक आस्था का अपमान नहीं है। बल्कि यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक मुद्दों में से एक के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक तरीका है। आस्था मन को पोषण देती है और रोजगार गरिमा, सुरक्षा और उद्देश्य प्रदान करता है। युवाओं को इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहना राष्ट्र की समस्या नहीं है। बल्कि, समस्या एक ऐसा वातावरण विकसित करना है जिसमें आस्था और अवसर सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ मौजूद हों। भारत में युवाओं की आबादी काफी अधिक है। इस जनसांख्यिकीय लाभ को देश की ताकत के रूप में देखा जाता है। हर साल लाखों युवा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से लाभकारी रोजगार की आशाओं और सपनों के साथ निकलते हैं। वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अनेकों नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं और भर्ती सूचनाओं का इंतजार करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन या तो उनके पास नौकरी नहीं है या वे अंशकालिक रूप से काम करते हैं। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं। बेरोजगारी आत्मविश्वास को कम कर सकती है, आर्थिक स्वतंत्रता में देरी कर सकती है, परिवारों पर दबाव बढ़ा सकती है और कुछ मामलों में निराशा और हताशा का कारण बन सकती है। कांवड़ यात्रा इस पीढ़ी से जुड़ी है, जो सबसे युवा पीढ़ियों में से एक है। ये लोग गांवों, कस्बों और शहरों से आते हैं। इनमें छात्र, किसानों के बच्चे, दिहाड़ी मजदूर, युवा पेशेवर और बेरोजगार स्नातक शामिल हैं। तीर्थयात्रा में उनकी भागीदारी उनके अपने विश्वास और संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए यह कहना कि बेरोजगारी लोगों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है या धार्मिक यात्राएं बेरोजगारी का कारण बनती हैं, सरल और अनुचित होगा। ये धारणाएं गलत हैं क्योंकि ये सामाजिक व्यवहार की जटिलता और आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखती हैं। हालांकि, यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले युवा जिस दृढ़ संकल्प और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हैं, वह अनुकरणीय है, और उनमें वह अनुशासन, सहनशीलता और प्रतिबद्धता भी है जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा, नवाचार, उद्यमिता, विनिर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और रोजगार के क्षेत्रों में, यदि समान अवसर उपलब्ध हों, तो यह विशाल मानव संसाधन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े प्रेरकों में से एक हो सकता है। न केवल पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा और श्रमिकों की अपेक्षाओं के बीच भी एक बड़ा अंतर है। आवश्यक कौशल रखने वाले स्नातकों के लिए भी रोजगार के अवसर अक्सर सीमित होते हैं, और उद्योगों में कुशल श्रमिकों की कमी है।

फकीरों की संसार

उदय कशोर साह

कविता

ये है फकीरों की अद्भुत संसार
यहाँ नहीं लगती दौलत की बाजार
हर जन मस्ती में यहाँ है चूर
चिन्ता फिक्र है जहाँ से कोसों दूर

दिल से है हर जन जन धनवान
लुट खसोट की नहीं कहीं है दुकान
हर शख्स अपने में है यहाँ मगरूर
वैमनस्यता को ना जगह है हुजूर

हर मन में बसा है शांति की अरमान
सब ग्रामीणों पे रब है यहाँ मेहरवान
हर चेहरे पे झलकता यहाँ पे नूर
खुदा को भी है ये नगर मंजूर

भाईचारा की सबका जहाँ कारीबार
बेईमानों की ना है कोई भी . व्यापार
ईमानदारी की है जहाँ रस्म । दस्तूर
हर जन जन पे छाई है हँसी की सरूर

काश ! इस जगत सा होता ये संसार
दुश्मन भी शर्म से हो जाता शर्मसार
दोस्ती के लिये हर मानव होता मजबूर
मस्ती में झूमता कण कण में मजबूर

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक ललित कुमार द्वारा वेलकम इंडिया प्रिन्टर्स, 1/26, साउथ साइड, जी टी रोड़, गाजियाबाद-201001 से मुद्रित कराकर ग्राउन्ड फ्लोर , दुर्गा टॉवर, आर.डी.सी राजनगर, गाजियाबाद 201002 से प्रकाशित किया । संपादक : ललित शर्मा
सम्पर्क सूत्रः 9891116568

किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा गाजियाबाद न्यायालय में ही होगा।

शारीरिक अक्षमता और बौद्धिक विकलांगता की जननी है, 'जातिगत आरक्षण'

एनके शर्मा
लेखक

भारत का संविधान समानता, न्याय और अवसर की अवधारणा पर आधारित है। इसी संविधान ने ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को आगे लाने के उद्देश्य से आरक्षण जैसी व्यवस्था का प्रावधान किया। उस समय इसकी परिकल्पना एक उपचारात्मक और संक्रमणकालीन उपाय के रूप में की गई थी, ताकि जिन वर्गों को सदियों तक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक वंचना झेलनी पड़ी, उन्हें मुख्यधारा में आने का अवसर मिल सके। किंतु सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद यह प्रश्न पहले से अधिक प्रासंगिक हो गया है–क्या वर्तमान स्वरूप में जातिगत आरक्षण अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, या वह स्वयं एक ऐसी स्थायी व्यवस्था बन चुका है, जिसकी समीक्षा लोकतंत्र के हित में आवश्यक है?

आज आरक्षण केवल एक सामाजिक नीति नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे संवेदनशील और सबसे प्रभावशाली चुनावी औजार बन चुका है। लगभग हर चुनाव में नई-नई आरक्षण घोषणाएँ होती हैं, नई श्रेणियों को जोड़ने की मांग उठती है और राजनीतिक दल इस विषय पर गंभीर सुधार की बजाय विस्तार का रास्ता चुनते दिखाई देते हैं। परिणाम यह हुआ कि आरक्षण पर तथ्यपरक विमर्श धीरे-धीरे भावनात्मक और राजनीतिक ध्रुवीकरण में बदलता गया।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या किसी लोकतंत्र में कोई भी नीति समीक्षा से ऊपर हो सकती है? यदि कर नीति, शिक्षा नीति, कृषि नीति, आर्थिक नीति और विदेश नीति की समीक्षा हो सकती है, तो आरक्षण व्यवस्था की भी निष्पक्ष समीक्षा क्यों नहीं? किसी नीति की समीक्षा को सामाजिक न्याय का विरोध मान लेना लोकतांत्रिक संवाद की भावना के विपरीत है। आरक्षण के आलोचकों का एक प्रमुख तर्क यह है कि जब अवसरों के वितरण में योग्यता के अतिरिक्त स्थायी पहचान भी निर्णायक कारक बन जाती है, तब प्रतियोगिता की प्रकृति बदल जाती है। उनका कहना है कि उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय का संतुलन बनाए रखना किसी भी आधुनिक राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा, प्रशासन और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता के प्रश्नों पर गंभीर चर्चा ही न हो सके, तो दीर्घकाल में संस्थागत क्षमता प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जाती है।

दूसरी ओर, आरक्षण के समर्थक तर्क देते हैं कि ऐतिहासिक वंचना की भरपाई के लिए विशेष अवसर आवश्यक हैं। इसलिए वास्तविक चुनौती इन दोनों उद्देश्यों–सामाजिक न्याय और उत्कृष्टता–के बीच संतुलन बनाने की है। आज एक और गंभीर प्रश्न सामने है–क्या आरक्षण का लाभ सबसे अधिक वंचित परिवारों तक पहुँच रहा है? सार्वजनिक विमर्श में वर्षों से यह चिंता व्यक्त होती रही है कि अपेक्षाकृत सक्षम परिवार बार-बार इसका लाभ उठा लेते हैं, जबकि अत्यंत गरीब और दूरदराज के अनेक लोग पीछे रह जाते हैं। यदि किसी भी कल्याणकारी नीति का लाभ वास्तविक लक्षित समूह तक नहीं पहुँच रहा, तो उस नीति की समीक्षा लोकतांत्रिक दायित्व बन जाती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आरक्षण का मुद्दा अब सामाजिक सुधार से अधिक चुनावी रणनीति का विषय बन चुका है। राजनीतिक दल शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक अवसरों के विस्तार पर उतनी ऊर्जा नहीं लगाते, जितनी नई आरक्षण घोषणाओं पर। इससे यह धारणा बल पाती है कि समस्या के मूल कारणों को दूर करने के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है। एक और विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या भारत वास्तव में जातिविहीन समाज की दिशा में बढ़ रहा है? यदि प्रत्येक सरकारी प्रक्रिया में नागरिक की जाति को बार-बार दर्ज करना आवश्यक बना रहे, तो क्या सामाजिक पहचान समय के साथ कमजोर होगी या और अधिक सुदृढ़? इस प्रश्न पर विभिन्न सामाजिक और संवैधानिक विचारकों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। यह बहस आज भी प्रासंगिक है। भारतीय संविधान समानता का भी संरक्षक है। समानता का अर्थ केवल अवसर देना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करना भी है जिनमें प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता का विकास कर सके। यदि प्राथमिक शिक्षा कमजोर हो, सरकारी विद्यालय संसाधनविहीन हों, उच्च शिक्षा महंगी होती जाए और रोजगार के अवसर सीमित हों, तो केवल आरक्षण सामाजिक न्याय की संपूर्ण समस्या का समाधान नहीं बन सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और आर्थिक अवसरों में निवेश के बिना सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। 21वीं सदी का भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, रक्षा अनुसंधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश कर चुका है। ऐसे समय में राष्ट्र को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो प्रतिभा को प्रोत्साहित करे, नवाचार को बढ़ावा दे और संस्थागत उत्कृष्टता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक को केवल उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अवसरों से वंचित न रहना पड़े। यह संतुलन ही लोकतांत्रिक नीति-निर्माण की वास्तविक कसौटी है। आज आवश्यकता किसी वर्ग को दोषी ठहराने की नहीं, बल्कि नीति की प्रभावशीलता का ईमानदार मूल्यांकन करने की है। यदि कोई व्यवस्था अपने घोषित उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम नहीं दे रही, तो उसका सुधार लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति है। समीक्षा का अर्थ समाप्ति नहीं होता; समीक्षा का अर्थ है–क्या नीति अपने लक्ष्य प्राप्त कर रही है, क्या उसमें संशोधन आवश्यक है, और क्या वह वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप है। भारतीय लोकतंत्र तब और परिपक्व होगा जब वह कठिन प्रश्नों से विमुख नहीं होगा। जातिगत आरक्षण पर बहस का उद्देश्य किसी समुदाय के अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और राष्ट्रीय उत्कृष्टता एक-दूसरे के पूरक बनें, प्रतिस्पर्धी नहीं। समय आ गया है कि राष्ट्र यह विचार करे कि क्या भविष्य की नीतियाँ वास्तविक वंचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और अवसरों के विस्तार पर अधिक केंद्रित हों। यदि भारत को विश्व की अग्रणी ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाना है, तो उसे सामाजिक न्याय और योग्यता–दोनों को संतुलित करने वाला साहसिक, पारदर्शी और समयानुकूल विमर्श अपनाना होगा। प्रश्न केवल आरक्षण का नहीं है; प्रश्न उस भारत का है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए निर्मित करना चाहते हैं। ऐसा भारत जहाँ किसी नागरिक की पहचान का सबसे बड़ा आधार उसकी जाति नहीं, बल्कि उसका चरित्र, उसका परिश्रम, उसकी प्रतिभा और राष्ट्र-निर्माण में उसका योगदान हो। यही वह संवैधानिक पुनर्विचार है, जो किसी भी परिपक्व लोकतंत्र की पहचान बन सकता है।

देश नशा-मुक्त हो या न हो, नारे जरूर नशा-मुक्त हैं

प्रो. आरके जैन
लेखक

कानून की सबसे लंबी सजा कभी अपराधी को नहीं, न्याय को मिलती है। नशा मुक्त भारत का मौजूदा अभियान इसी सजा के बीच अपनी सफलता का उत्सव मना रहा है। सौ-सप्ताहीय कार्यक्रम, युवाओं की शपथ, जागरूकता यात्राएं और सरकारी संकल्प यह भरोसा जगाते हैं कि नशे के खिलाफ निर्णायक संघर्ष चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर एनडीपीएस कानून से जुड़े लगभग 3.96 लाख मुकदमे अदालतों में वर्षों से लंबित हैं। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का मौन बयान है, जहां न्याय की हर देरी अपराध का आत्मविश्वास बढ़ाती है। अभियान सक्रियता का आभास देते हैं, जबकि अदालतों की ठहरी हुई फाइलें बताती हैं कि व्यवस्था अपनी ही रफ्तार से हार रही है। नशा अब कानून से नहीं, कानून की देरी से सबसे अधिक सुरक्षित हो चुका है।

अदालतें जब समय हारने लगती हैं, तब अपराधी मुकदमे नहीं, अवसर गिनते हैं। पंजाब में लगभग साठ हजार और केरल में करीब पचास हजार एनडीपीएस मामले वर्षों से लंबित हैं। विशेष अदालतें जरूरत से कम हैं, न्यायाधीश सीमित हैं और मुकदमों की चाल इतनी सुस्त है कि अनेक आरोपी जमानत पर बाहर आकर अपना तंत्र फिर खड़ा कर लेते हैं। यहीं न्याय की देरी अपराध का सबसे विश्वसनीय संरक्षण बन जाती है। जितने अधिक मामले दर्ज होते हैं, उतना ही बैकलॉग बढ़ता है और उतना ही यह विश्वास गहराता है कि गिरफ्तारी अंत नहीं, केवल एक औपचारिक पड़ाव है। नशा मुक्त अभियान अपराध को सामाजिक अभिशाप बताते हैं, लेकिन न्यायिक विलंब उसी अभिशाप की उम्र बढ़ाता रहता है। यह ऐसा विरोधाभास है, जिसे अब कोई सरकारी उपलब्धि ढक नहीं सकती। नशे का बाजार अब गलियों से निकलकर मोबाइल की स्क्रीन पर फल-फूल रहा है। इतिहास में पहली बार गली हार गई और स्क्रीन जीत गई। एन्क्रिप्टेड ऐप, डार्क वेब और सोशल मीडिया के बंद समूहों ने खरीद-बिक्री को इतनी गोपनीयता दे दी है कि ग्राहक को घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जिन कॉलेजों में नशा विरोधी रैलियां निकलती हैं, वहीं के छात्र मोबाइल से सप्लायर तक पहुंच जाते हैं। पुलिस पुराने तस्करों को पकड़ती है, लेकिन तब तक डिजिटल दुनिया नए चेहरे तैयार कर चुकी होती है। हमारी कार्रवाई आज भी एनालॉग सोच में अटकी है, जबकि अपराध पूरी तरह डिजिटल हो चुका है।

यही फासला अभियानों को प्रतीक और नशे को सुविधा बना देता है। जब तकनीक ही अपराध का सबसे भरोसेमंद माध्यम बन जाए, तब पोस्टर और शपथ उसकी रफ्तार नहीं रोक सकते। जब ईमानदार श्रम की कीमत घटने लगे और जोखिम सबसे लाभकारी रोजगार बन जाए, तभी अपराध कारोबार बन जाता है। बेरोजगारी, त्वरित कमाई का आकर्षण और फैलता अवैध धन युवाओं को नशे की सप्लाई चेन में खींच लाता है। छोटे वाहक गिरफ्तार होते हैं, उनके परिवार बिखरते हैं और समाज उन्हें अपराध का चेहरा मान लेता है। उधर बड़े तस्कर कमजोर अभियोजन, लंबी कानूनी प्रक्रिया और तकनीकी खामियों की आड़ में बच निकलते हैं। अभियान युवाओं को नैतिकता का उपदेश देते हैं, लेकिन व्यवस्था सम्मानजनक आर्थिक विकल्प नहीं दे पाती। नशा केवल लत नहीं, कुछ परिवारों की छिपी आजीविका बन जाता है। जब तक यह आर्थिक सच स्वीकार नहीं किया जाएगा, हर अभियान बीमारी नहीं, उसके लक्षणों का उपचार करेगा। आंकड़े कभी-कभी ऐसी जीत का उत्सव मनाते हैं, जिसे सच्चाई चुपचाप हार में बदल चुकी होती है। हर वर्ष प्रवर्तन एजेंसियां बड़ी जब्तियों का दावा करती हैं। मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और इसे सफलता बताया जाता है। लेकिन इतनी बरामदगी के बाद भी यदि बाजार में नशा पहले जैसी सहजता से उपलब्ध है और कीमतों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव नहीं आता, तो स्पष्ट है कि एक सप्लाई लाइन की जगह दूसरी खड़ी हो चुकी है। तब बरामदगी उपलब्धि नहीं, बल्कि लगातार रास्ते बदलते विशाल नेटवर्क का प्रमाण बन जाती है। जब्ती के आंकड़े जितने बढ़ते हैं, प्रश्न उतना बड़ा होता है कि उपलब्धता क्यों नहीं घट रही। सफलता की असली कसौटी बरामद माल नहीं, घटती मांग और कठिन होती पहुंच होनी चाहिए। हर अभियान की सबसे बड़ी चूक यह है कि वह घरों के भीतर पसरे सन्नाटे को सुन ही नहीं पाता। परिवारों की त्रासदी सबसे कम दिखाई देती है, जबकि सबसे अधिक वही भुगतते हैं। एक ओर उन्हें जागरूकता कार्यक्रमों में नशे से दूर रहने की सीख मिलती है, दूसरी ओर वही नशा डिजिटल रास्तों से उनके बच्चों तक पहुंच जाता है। परिवार का कोई सदस्य नशे के आरोप में वर्षों अदालतों के चक्कर काटे, तो आर्थिक बोझ, सामाजिक अपमान और मानसिक थकान पूरे घर को तोड़ देती है। न्याय में देरी केवल एक मुकदमे को लंबा नहीं करती, बल्कि व्यवस्था से नागरिक का भरोसा भी कम करती है। नशा छोड़ने का संदेश हवा में तैरता रहता है, जबकि नशे की उपलब्धता घर के भीतर प्रवेश करती रहती है। यही सबसे भयावह असमानता है, जिसे कोई नारा ढंक नहीं सकता। किसी भी अभियान का अंतिम फैसला नारों से नहीं, जमीन की हकीकत से होता है। यदि विशेष अदालतें पर्याप्त नहीं होंगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट महीनों अटकी रहेंगी, डिजिटल सप्लाई चेन पर ठोस रोक नहीं लगेगी और छोटे मामलों के लिए प्रभावी सुधार व्यवस्था नहीं होगी, तो अभियान व्यवस्था की कमजोरियों पर परदा डालेंगे। अभियान जितना बड़ा होगा, भ्रम उतना गहरा होगा। नशा-मुक्त भारत की असली पहचान शपथों से नहीं, बल्कि इस बात से होगी कि क्या नशा कठिनाई से उपलब्ध हो रहा है। आज तस्वीर उलटी है–उपलब्धता और अभियान, दोनों बढ़ रहे हैं। इसलिए लड़ाई का केंद्र बदलना होगा। शब्दों की मशाल नहीं, न्याय की गति, तकनीक की तैयारी और प्रशासनिक ईमानदारी ही नशे को सुलभ बनाने वाली सुविधाएं तोड़ सकती हैं। सुविधा टूटते ही अभियान पहली बार सच के साथ खड़े दिखाई देंगे।

भ्रष्टाचार का अदृश्य कर: सबसे भारी कीमत गरीब क्यों चुकाता है?

किशन भावनानीं
लेखक

वैश्विक स्तरपर आज के डिजिटल युग में भ्रष्टाचार केवल सरकारी फाइलों,बंद कमरों,रिश्वतखोरी या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग तक सीमित विषय नहीं रह गया है।अब एक अधूरी सड़क का वीडियो,जर्जरस्कूल की तस्वीर,वर्षों से बंद पड़ा अस्पताल,अधूरा पुल, अनुपयोगी सरकारी भवन या किसी नागरिक की शिकायत कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। पहले नागरिक भ्रष्टाचार की शिकायत करते थे, फिर मीडिया उसे प्रकाशित करता था,उसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय होती थीं और अंततः राजनीतिक या प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद की जाती थी। लेकिन डिजिटल युग में नागरिक स्वयं कैमरा,रिपोर्टर, तथ्य-संग्रहकर्ता,जनमत निमार्ता और कभी-कभी राजनीतिक प्रतिनिधि भी बन रहा है। सोशल मीडिया ने जनता को आवाज तो दी है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा किया है, क्या डिजिटल निगरानी वास्तव में जवाबदेही बढ़ाएगी या केवल वायरल लोकप्रियता की राजनीति को जन्म देगी? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि डिजिटल अभियानों को तथ्य, प्रमाण, स्वतंत्र जांच और संस्थागत सुधार से कितना जोड़ा जाता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि रिश्वत को अदृश्य कर कहना इसलिए उचित है, क्योंकि यह अक्सर कानून द्वारा निर्धारित कर नहीं होती, फिर भी नागरिक को सेवा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। अंतर यह है कि वैध कर सार्वजनिक बजट में दर्ज होता है और उसके उपयोग पर लोकतांत्रिक निगरानी संभव होती है, जबकि रिश्वत निजी लाभ में चली जाती है और सार्वजनिक व्यवस्था को भीतर से कमजोर करती है।इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब, निम्न-मध्यमवर्गीय और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। संपन्न व्यक्ति के लिए एक छोटी अवैध राशि आर्थिक असुविधा हो सकती है, लेकिन सीमित आय वाले परिवार के लिए वही राशि भोजन, शिक्षा, दवा या यात्रा के बजट को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता को बढ़ाने वाला तंत्र भी बन जाता है।संयुक्त राष्ट्र की द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भ्रष्टाचार औररिश्वतखोरी विकासशील देशों में गरीबों पर अमीर देशों की तुलना में तीन गुना अधिक वित्तीय बोझ डालती है,जिससे 17 प्रतिशत आबादी सीधे प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कड़े कानूनी ढांचे के बावजूद भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के खराब कार्यान्वयन से संस्थागत जवाबदेही कमजोर हो रही है। अब विश्व सहित भारत से यह उम्मीद की जाती है कि भ्रष्टाचार कानून का क्रियान्वयन सख़्ती से किया जाएगा? या फिर जंतर मंतर पर जेन जेड के खिलाफ पेपर लीकआंदोलन की तरह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की रास्ता देखी जाएगी।

साथियों, संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार, जिन देशों के लिए हालिया और तुलनीय आंकड़े उपलब्ध हैं,वहां सार्वजनिक अधिकारियों से संपर्क करने वाले लगभग 17 प्रतिशत लोगों ने बताया कि पिछले 12 महीनों के दौरान उनसे रिश्वत मांगी गई या सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ी। रिपोर्ट के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि निम्न-आय वाले देशों में रिश्वतखोरी का प्रभाव उच्च-आय वाले देशों की तुलना में अधिक व्यापक और गंभीर है। मध्य एवं दक्षिण एशिया में भी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के दौरान रिश्वत की समस्या चिंता का विषय बनी हुई है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक अनियमितता या आर्थिक अपराध नहीं,बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नागरिक अधिकारों से जुड़ी वैश्विक चुनौती है।जब किसी नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा पुलिस, भूमि, प्रमाण-पत्र, लाइसेंस या अन्य आवश्यक सरकारी सेवा के लिए वैध शुल्क के अतिरिक्त अवैध भुगतान करना पड़ता है, तो रिश्वत एक प्रकार के ह्लअदृश्य करह्व में बदल जाती है। इसका सबसे अधिक बोझ गरीब, निम्न- आय और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कठोर कानून के साथ पारदर्शी प्रशासन, डिजिटल जवाबदेही, स्वतंत्र निगरानी, सुरक्षित शिकायत व्यवस्था और सटिका से समयबद्ध कार्रवाई भी आवश्यक है। साथियों भ्रष्टाचार का एक और अधिक गंभीर पक्ष वह है, जो अक्सर बड़े घोटालों की सुर्खियों में दिखाई नहीं देता, आम नागरिक द्वारा दिया जाने वाला छोटा या मजबूरी का भुगतान।किसी प्रमाणपत्र, लाइसेंस,पुलिस कार्यवाही, भूमि संबंधी सेवा,स्वास्थ्य सुविधा या अन्य सार्वजनिक सेवा के लिए यदि नागरिक से अनुचित धन मांगा जाता है, तो यह केवल व्यक्तिगत आर्थिक नुकसान नहीं होता; यह राज्य और नागरिक के बीच विश्वास को कमजोर करता है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 16 में शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं के साथ भ्रष्टाचार एवं रिश्वत को कम करने को विशेष महत्व दिया गया है।

एसडीजी -16 का उद्देश्य प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का निर्माण करना है, क्योंकि विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब नागरिकों को सेवाएं निष्पक्ष और समान रूप से उपलब्ध हों। साथियों, बदलती व्यवस्था का एक असाधारण उदाहरण आज 4 अगस्त 2026 को कोलंबिया में सामने आया, जहां भ्रष्टाचार और उपेक्षित सार्वजनिक परियोजनाओं को उजागर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता लुइस कार्लोस रूआ ने सफेद हाथी की पोशाक पहनकर सीनेटर के रूप में शपथ ली। उन्होंने बिना किसी पारंपरिक और बड़े राजनीतिक प्रचार के लगभग 1,24,000 वोट हासिल किए और सीनेट के लिए चुने गए। उनका इस वेशभूषा में संसद पहुँचना यह दिखाने के लिए था कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी इस अनोखी निगरानी को अब संसद के भीतर से भी जारी रखेंगे, उनका यह प्रतीक उन महंगी, अधूरी, अनुपयोगी या कुप्रबंधित सार्वजनिक परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिन पर जनता का धन खर्च तो होता है, लेकिन उनका अपेक्षित लाभ जनता तक नहीं पहुंचता। सोशल मीडिया पर सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक ढांचों की कमियों को सामने लाने वाले उनके अभियानों ने उन्हें लोकप्रिय बनाया और वे लगभग 1.24 लाख मतों के साथ कोलंबिया के प्रमुख निर्वाचित सीनेटरों में शामिल हुए।यह घटना केवल एक व्यक्ति के संसद पहुंचने की कहानी नहीं है; यह दुनिया की राजनीति में उभर रहे सटीकता से एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। साथियों संयुक्त राष्ट्र के भ्रष्टाचार -संबंधी वैश्विक संकेतक भी यह मानते हैं कि रिश्वत की समस्या को केवल दर्ज मामलों से नहीं मापा जा सकता। एसडीजी लक्ष्य 16.5 के अंतर्गत यह देखा जाता है कि सार्वजनिक अधिकारी से संपर्क करने वाले कितने लोगों या व्यवसायों ने पिछले 12 महीनों में रिश्वत दी या उनसे रिश्वत मांगी गई।

निर्माणाधीन पुलिया का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कार्य में गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण के दिए निर्देश

नौगढ़-सोहांस मार्ग पर चल रहे कार्य का लिया जायजा, मार्ग जल्द तैयार कर आवागमन शुरू कराने पर दिया जोर

वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मंगलवार को नौगढ़-सोहांस मार्ग पर निमार्णाधीन पुलिया का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिया की छत की ढलाई का कार्य प्रगति पर मिला। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता, कार्य की समयसीमा तथा तकनीकी मानकों की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि पुलिया का निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एवं पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और निर्माण कार्य को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुलिया निर्माण के साथ-साथ एप्रोच मार्ग का निर्माण भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सड़क पर यातायात निर्बाध रूप से संचालित होना चाहिए। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्ग पर संभावित ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए जाएं तथा आवश्यक स्थानों पर चेतावनी एवं दिशा-सूचक संकेतक बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम हो और यात्रियों को सुरक्षित सफर का लाभ मिल सके।

कांग्रेस ने अल्पसंख्यक विभाग के पुनर्गठन को लेकर की समीक्षा बैठक, 2027 चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन

वेलकम इंडिया राजेंद्र सिंह वरिष्ठ

हापुड़। दिल्ली रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के पुनर्गठन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी रूबी खान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक नसीम कुरैशी तथा सह प्रभारी महमूद खान ने संगठन को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की।बैठक को संबोधित करते हुए रूबी खान ने कहा कि कांग्रेस में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी निर्णायक भूमिका रही है। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आ'ान किया।पश्चिमी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के संयोजक नसीम कुरैशी ने कहा कि प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग का नए सिरे से पुनर्गठन किया जा रहा है, जिससे संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कार्यकताओं से एकजुट होकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आ'ान किया। वहीं शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। उन्होंने लोगों से संविधान और देशहित को ध्यान में रखकर मतदान करने की अपील की।बैठक में मेरठ एमएलसी प्रत्याशी एडवोकेट विक्रांत त्यागी, सीमा शर्मा, वाई.के. शर्मा, डॉ. वी.सी. शर्मा, रश्मि चौधरी, राजकुमार जौहरी, एडवोकेट शहजादा चौधरी, रामलाल आर्य, यशपाल ढीलोर, सुखपाल गौतम, गौरव गर्ग, नरेश भाटी, अमित अग्रवाल, कपिल शर्मा, लोकपाल सागर, आकाश त्यागी, खुशनूद अली, अफजाल आढ़ती, कुसुमलता, शादाब सैफी, यूसुफ हवारी, गुलफाम कुरैशी, आवेश, विनोद जाटव, सचिन गोयल, विजय कुमार, गोपाल भारती एवं महबूब अली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हापुड़ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद, थाना प्रभारी मनीष चौहान ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

वेलकम इंडिया/राजेंद्र सिंह वरिष्ठ

हापुड़। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए हापुड़ पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी हापुड़ नगर मनीष चौहान लगातार कांवड़ मार्गों, शिविरों, शिव मंदिरों तथा संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं।निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी ने पुलिस बल को पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए और कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने शिविर संचालकों एवं स्थानीय लोगों से भी संवाद कर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। हापुड़ पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित एवं सुगमता के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकें।

रोबोटिक फिजियोथेरेपी से दर्द को मात, मरीजों को मिल रही नई उम्मीद

वेलकम इंडिया संवाददाता

सिद्धार्थनगर। बदलती जीवनशैली और बढ़ते शारीरिक श्रम के कारण मांसपेशियों, नसों और जोड़ों के दर्द से हर आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए अब रोबोटिक फिजियोथेरेपी नई उम्मीद बनकर उभर रही है। जिला मुख्यालय के उसका रोड स्थित सिद्धार्थ फिजियोथेरेपी सेंटर में आधुनिक रोबोटिक तकनीक के माध्यम से मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिससे उन्हें दर्द से राहत मिलने के साथ शरीर की गतिविधियां भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं।

सेंटर में उपचार करा रहे बी.पी. प्रसाद ने बताया कि दीवार से चोट लगने के बाद उनका हाथ लगभग काम करना बंद कर दिया था। लंबे समय तक सामान्य जीवन जीने की उम्मीद कम हो गई थी, लेकिन रोबोटिक फिजियोथेरेपी शुरू होने के बाद हाथ में धीरे-धीरे मूवमेंट आने लगा है। उनका कहना है कि उपचार से लगातार सुधार हो रहा है और उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद है। सिद्धार्थ फिजियोथेरेपी सेंटर के संचालक डॉ. सुभाष यादव ने बताया कि रोबोटिक मशीन हाथ और पैरों की एक्सरसाइज अत्यंत सटीक ढंग से कराती है। यह तकनीक विशेष रूप से उन मरीजों के लिए उपयोगी है, जो स्वयं अंगों को हिला-डुला नहीं पाते। उन्होंने बताया कि नियंत्रित और बार-बार होने वाली एक्सरसाइज से मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय बेहतर होता है, जिससे मरीज तेजी से रिकवरी की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में सेंटर की ओपीडी में प्रतिदिन 60 से 70 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने छपकोली मंदिर में किया जलाभिषेक, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

वेलकम इंडिया राजेंद्र सिंह वरिष्ठ

हापुड़। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मंगलवार को जिलाधिकारी वं पुलिस अधीक्षक ने बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित छपकोली मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक किया। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने मंदिर परिसर एवं आसपास की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग तथा मंदिर परिसर में कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क एवं प्रभावी रहे।इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर, थाना प्रभारी बाबूगढ़ प्रवीण कुमार सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

श्रावण मास /कांवड़ यात्रा: बाबूगढ़ पुलिस अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था का थाना प्रभारी ने लिया जायजा

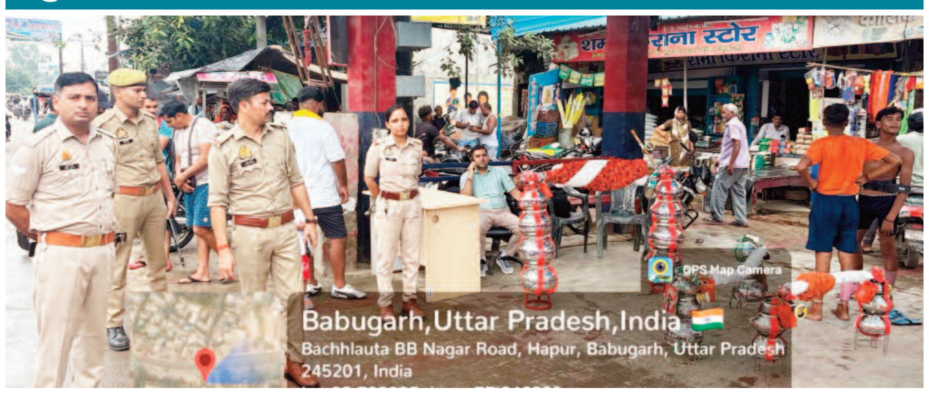

वेलकम इंडिया राजेंद्र सिंह वरिष्ठ

हापुड़। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए हापुड़ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी बाबूगढ़ प्रवीण कुमार द्वारा कांवड़ मार्गों, शिविरों, धार्मिक स्थलों तथा संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है।थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने पुलिस बल के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का जायजा लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। हापुड़ पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि यात्रा के दौरान यातायात एवं सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके।

सूखे नल, प्यासे लोग: ग्राम कुआँखेड़ा में जल जीवन मिशन दम तोड़ता नजर आया

डेढ़ वर्ष से बंद पड़ी पेयजल आपूर्ति, ग्रामीणों में आक्रोश; शिवसेना जिलाध्यक्ष ने किया स्थलीय निरीक्षण, व्यवस्था पर उठाए सवाल

वेलकम इंडिया संवाददाता

धामपुर। क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुआँखेड़ा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना ग्रामीणों के लिए उम्मीदों के बजाय निराशा का कारण बन गई है। गांव में नमामि गंगे एवं उत्तर प्रदेश जलापूर्ति विभाग द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व पेयजल आपूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया गया था। पाइपलाइन बिछाने और टंकी बनने के बाद कुछ समय तक घरों में पानी की आपूर्ति हुई, लेकिन पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं आई, जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित जूनियर इंजीनियर एवं विभागीय अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर शिवसेना जिलाध्यक्ष चौधरी संजय राणा अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और ओवरहेड टैंक सहित जलापूर्ति व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ऊषा कौर, जमीर सिंह, सुखदयाल सिंह, आशीष, फतेह सिंह, कृष्णा रानी, मोनिका रानी, राजरानी, मुख्तियार सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, सुबा सिंह, जसपाल सिंह, श्रवण कुमार, प्रभुजोत सिंह, सरजीत कौर, जसवंत सिंह, जीत सिंह, जोगिंदर सिंह, जगतार सिंह, गुरमीत सिंह, परगट सिंह, हरजीत सिंह और कुलवंत सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि गांव में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि गांव में एक भी इंडिया मार्का हैंडपंप उपलब्ध नहीं है। निजी बोरिंग और नल लगवाना आम ग्रामीण की आर्थिक क्षमता से बाहर है।

ग्रामीणों ने बताया कि व्यक्तिगत नलों से भी गंदा और दूषित पानी निकलता है। मजबूरी में वे रात के समय पानी भरकर उसे घड़ों में रखते हैं तथा उसमें फिटकरी और चूना डालकर शुद्ध करने के बाद अगले दिन पीने के लिए उपयोग करते हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से शुद्ध पेयजल उपलब्ध न होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान चौधरी संजय राणा ने ओवरहेड टैंक परिसर की बदहाल स्थिति पर भी गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने देखा कि परिसर में घास और कंटीली झाड़ियां उगी हुई हैं तथा रखरखाव के लिए तैनात कर्मचारी ने वहां अपने कृषि उपकरण रखने का स्थान बना लिया है। वहीं, सोलर पैनल, मोटर और अन्य उपकरण जंग लगने से खराब होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं।

चौधरी संजय राणा ने कहा कि जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, लेकिन कई स्थानों पर भ्रष्टाचार, रखरखाव की कमी, अधूरी व्यवस्थाओं और समय पर जलापूर्ति न होने के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग से तत्काल जलापूर्ति बहाल करने और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। निरीक्षण के दौरान महेंद्र सिंह सिरोही, मनवीर सिंह यादव, सरदार कुलदीप सिंह, सतीश सिंह, सत्यवीर सिंह सैनी, नरेंद्र सिंह, सरदार अमरीक सिंह, हरवीर सिंह, गुरमीत कौर, सरजीत कौर, राधिका देवी, विजयलक्ष्मी रावत सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बीसीए ओरिएंटेशन-कम-इंडक्शन 2k26 का शुभारंभ, तकनीकी शिक्षा और नवाचार पर दिया गया जोर

वेलकम इंडिया/ राजेंद्र सिंह वरिष्ठ

हापुड़। स्थानीय जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हापुड़ में मंगलवार को प्रोफेशनल प्रोग्राम बीसीए के सात दिवसीय ओरिएंटेशन-कम-इंडक्शन 2K26 कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के फाउंडर चेयरमैन राकेश सिंघल, सचिव डॉ. रोहन सिंघल, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. आयुष सिंघल, महानिदेशक प्रो. (डॉ.) सुभाष गौतम, जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाचार्या डॉ. निधि मलिक, प्राचार्य डॉ. धीरज सैनी तथा मुख्य अतिथि एवं मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के कुलपति प्रो. (डॉ.) पी.के. दशोरा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। महानिदेशक प्रो. (डॉ.) सुभाष गौतम ने बताया कि सात दिवसीय इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम के माध्यम से बीसीए के नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं को संस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था, तकनीकी संसाधनों एवं विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराया जाएगा।

मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. आयुष सिंघल ने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास, तकनीकी दक्षता और सकारात्मक सोच विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि देश के विकास में कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्थान के फाउंडर चेयरमैन राकेश सिंघल ने विद्यार्थियों को अनुशासन, नैतिक मूल्यों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि संस्थान में आधुनिक कंप्यूटर लैब, समृद्ध पुस्तकालय और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से जिज्ञासु बने रहने और किसी भी समस्या या शंका का समाधान शिक्षकों से प्राप्त करने का आ'ान किया। मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) पी.के. दशोरा ने कहा कि 21वीं सदी में केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी दक्षता, नवाचार और डिजिटल कौशल भी बेहद आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकों का युग है, जिसमें युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप स्वयं को तैयार करना होगा। कार्यक्रम में डॉ. आयुष सिंघल और डॉ. रोहन सिंघल ने बताया कि संस्थान भविष्य में भी छात्रों के ज्ञानवर्धन के लिए अतिथि व्याख्यान, स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, टेक्निकल क्लब, हैकाथॉन और इंडस्ट्री इंटीग्रेशन जैसी गतिविधियों का आयोजन करता रहेगा। कार्यक्रम के दूसरे चरण में डीएसडब्ल्यू विशाल त्यागी ने संस्थान की अकादमिक गतिविधियों की जानकारी दी, जबकि परीक्षा एवं एंटी-रैगिंग प्रभारी अंकित नागर ने संस्थान के नियमों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया। कार्यक्रम में संस्थान के शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नवप्रवेशित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

ओवरस्पीड वाहनों पर अब कड़ी नजर, सिद्धार्थनगर पुलिस को मिले दो नए दोपहिया इंटरसेप्टर वाहन

वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के उद्देश्य से मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने पुलिस कार्यालय परिसर से दो नए दोपहिया इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के विभिन्न मार्गों पर ओवरस्पीड वाहनों की निगरानी करेंगे। निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद, क्षेत्राधिकारी सदर विश्वजीत सौरयान, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी, प्रभारी यातायात अजय कुमार सिंह यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। यातायात पुलिस ने लोगों से गति सीमा का पालन करने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की।

मुख्यमंत्री धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र को दी 17.80 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात

मसूरी के विकास को मिलेगी नई रफ्तार: पुष्कर सिंह धामी

वेलकम इंडिया संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पुरकुल में लगभग 17 करोड़ 80 लाख रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक पुण्डीर की स्मृति में निर्मित नवनिर्मित सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित एवं समग्र विकास के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वेडिंग डेस्टिनेशन या पर्यटन की चर्चा होती है, तो पहाड़ों की रानी मसूरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनमोहक वादियां देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पर्यटन से स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत होती है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलती है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार मसूरी को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पुरकुल में सैन्य धाम का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के वीर सैनिकों की

गौरवगाथा को नई पहचान देगा। इसके अलावा मसूरी रोपवे परियोजना के लोअर टर्मिनल तक लगभग 13 किलोमीटर मुख्य मार्ग के उच्चीकरण का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा यातायात व्यवस्था सुगम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत गंगोल-पंडितवाड़ी पेयजल योजना के माध्यम से अनेक गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। इससे हजारों ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हुई है। उन्होंने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़क संपर्क को और मजबूत बनाने के लिए मालदेवता लाल पुल से सिल्ला-मोलधार होते हुए सुआखोली तक सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) योजना के तहत कराया जा रहा है। यह परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी काफी लाभकारी सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत रिखोली के सोलाग गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर विद्युत सुविधा उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से जन-धन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सहस्त्रधारा क्षेत्र में बाल्दी नदी के दोनों किनारों पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई में बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त न्यू कैंट रोड क्षेत्र में भी सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिससे बरसात के दौरान संभावित नुकसान को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन सभी विकास परियोजनाओं के पूर्ण होने से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन, सड़क संपर्क, पेयजल, विद्युत और आपदा सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में बदलाव, 17 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द

वेलकम इंडिया संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 17 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। वहीं, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सात नए राजनीतिक दलों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की राजनीतिक पार्टी को भी चुनाव आयोग से पंजीकरण प्राप्त हो गया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के समय उत्तराखंड में कुल 42 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सक्रिय थे। चुनाव आयोग की समीक्षा में पाया गया कि इनमें से 17 दल पिछले छह वर्षों से किसी भी चुनाव में शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान कई दल अपने पंजीकृत कार्यालयों के पते पर मौजूद भी नहीं मिले। चुनाव आयोग की जांच में यह भी सामने आया कि कई राजनीतिक दलों ने निर्धारित समय पर वित्तीय विवरण (फाइनेंशियल रिटर्न), अंशदान रिपोर्ट तथा आंतरिक संगठनात्मक चुनावों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी जमा नहीं किए। चुनाव आयोग के नियमों का लगातार उल्लंघन करने और निष्क्रिय पाए जाने के कारण इन दलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी संबंधित दलों को निष्क्रिय अथवा संदिग्ध पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल मानते हुए नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें अपना पक्ष रखने और अपने अस्तित्व से जुड़े प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर भी दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने इन 17 दलों का पंजीकरण निरस्त कर उन्हें आधिकारिक सूची से हटा दिया।

शारदा नदी का फिर बढ़ा कहर, गन्ने की लहलहाती फसल समेत किसानों की जमीन समाई; ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

वेलकम इंडिया संवाददाता

पूरनपुर/पीलीभीत। ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्राम हजारा में शारदा नदी का कटान एक बार फिर भयावह रूप लेने लगा है। लगातार हो रहे भू-कटान से किसानों में दहशत का माहौल है। नदी ने आधा दर्जन से अधिक किसानों की कृषि भूमि को गन्ने की लहलहाती फसल समेत अपनी आगोश में समा लिया है। कटान की रफ्तार तेज होने से ग्रामीणों को अब अपने गांवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराता दिखाई दे रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि शारदा नदी के मुहाने पर ग्राम हजारा, शास्त्रीनगर, सिद्धनगर और भरतपुर सहित कई गांव बसे हुए हैं। यदि समय रहते प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में इन गांवों पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं धनाराघाट पर शारदा

नदी में करोड़ों रुपये की लागत से निमार्णाधीन पुल पर भी कटान का खतरा मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है।सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण शारदा नदी के किनारे एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन कर शासन-प्रशासन से तत्काल कटान रोकने के लिए स्थायी सुरक्षा कार्य शुरू कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष भी दर्जनों किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि और फसलें शारदा नदी में समा गई थीं। उस समय क्षेत्रीय विधायक बाबूराम पासवान से मिलकर समस्या के समाधान की मांग की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिणामस्वरूप इस वर्ष फिर से नदी का कटान शुरू हो गया है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं।

ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि कटान प्रभावित क्षेत्र का तत्काल सर्वे कराकर तटबंध, बोल्डर पिचिंग तथा अन्य सुरक्षा कार्य कराए जाएं, जिससे किसानों की भूमि, फसल और गांवों को बचाया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भयावह हो सकती है। प्रदर्शन के दौरान राकेश यादव, ग्राम पंचायत सदस्य परमात्मा, रामचंद्र लाल, राधेश्याम, रामलखन, रामकिशोर, रजनीश कुशवाहा, लक्ष्मण, पुतूलाल, हरसुवरन लाल सहित बड़ी संख्या में प्रभावित किसान एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

एसडीएम ने कांवड़ मार्ग का किया स्थलीय निरीक्षण, प्रशासन अलर्ट

विद्युत लाइनों और उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था परखी, जर्जर तारों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश

वेलकम इंडिया संवाददाता

पूरनपुर/पीलीभीत। कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके सुगम आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपजिलाधिकारी पूरनपुर ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड एवं संबंधित अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्ग तथा प्रमुख स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विद्युत व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए संभावित जोखिम वाले स्थानों को चिन्हित किया।उपजिलाधिकारी ने कांवड़ मार्ग पर विद्युत लाइनों, विद्युत पोलों, ट्रांसफार्मरों सहित अन्य विद्युत उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया। उन्होंने अधिशासी अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत आपूर्ति

व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और सुचारु रहनी चाहिए। मार्ग में कहीं भी जर्जर अथवा झूलते हुए विद्युत तार दिखाई देने पर उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जाए, ताकि कांवड़ियों और आम राहगीरों को किसी प्रकार का खतरा न हो। उन्होंने खुले विद्युत उपकरणों तथा अन्य संभावित दुर्घटना वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत विभाग को आवश्यक निवारक उपाय तत्काल पूरा करने को कहा, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

एसडीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत विभाग की टीमें लगातार सक्रिय रहें और किसी भी आपात स्थिति की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाए और किसी भी कमी को तत्काल दूर कराया जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें और अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करें। प्रशासन का उद्देश्य है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।

ट्रांसफॉर्मर पर लिपटी बेल बनी जानलेवा, हो सकता है हादसा

वेलकम इंडिया संवाददाता

बीसलपुर/पीलीभीत। कस्बा चुर्रा सकतपुर क्षेत्र के गांव किशनी में बिजली के ट्रांसफॉर्मर पर लिपटी बेल इन दिनों ग्रामीणों और राहगीरों के लिए गंभीर खतरे का सबब बनी हुई है। परेवाझकिशनी मार्ग पर स्थित ट्रांसफॉर्मर पर बेल के फैल जाने से बिजली के उपकरणों के आसपास जोखिम बढ़ गया है। ग्रामीणों को आशंका है कि बेल के कारण ट्रांसफॉर्मर में स्पार्किंग या विद्युत फाल्ट होने की स्थिति में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफॉर्मर गांव के मुख्य मार्ग के किनारे लगा हुआ है, जहां से दिनभर बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। इसके अलावा आसपास रहने वाले ग्रामीणों और किसानों को भी इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। ऐसे में ट्रांसफॉर्मर पर लिपटी बेल को लेकर लोगों में लगातार भय बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते बेल को नहीं हटाया गया और ट्रांसफॉर्मर की जांच कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था

नहीं की गई तो किसी दिन गंभीर दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों के अनुसार इस समस्या की जानकारी कई बार बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जा चुकी है। इसके बावजूद अभी तक ट्रांसफॉर्मर से बेल हटाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ग्रामीणों में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी भी बढ़ रही है। ग्रामीण विनीत कुमार, महावीर, शिवचरण, जितेंद्र, रामस्वरूप, गंगाराम, विनोद कुमार सहित अन्य ग्रामीणों ने बिजली विभाग से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर टीम भेजने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि ट्रांसफॉर्मर पर लिपटी बेल को जल्द हटाया जाए और विद्युत उपकरणों की तकनीकी जांच कर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ और कोई हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। ग्रामीणों ने जनहित में बिजली विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए लापरवाही के बजाय समय रहते कदम उठाना बेहद जरूरी है।

भाजपा जिला कार्यशाला में हर घर तिरंगा अभियान की रूपरेखा तय

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर होंगे कार्यक्रम

वेलकम इंडिया संवाददाता

पीलीभीत। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर मंगलवार को 'हर घर तिरंगा-तिरंगा यात्रा' अभियान के तहत जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य ने की, जबकि संचालन अभियान संयोजक एवं जिला महामंत्री मंगली प्रसाद वर्मा ने किया।जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के आ'ान पर 13 अगस्त को जनपद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर गोष्ठी एवं मौन जुलूस आयोजित होगा। वहीं 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर और प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान महापुरुषों के स्मारकों पर स्वच्छता अभियान भी संचालित किया जाएगा।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं जिला प्रभारी गुलशन

आनंद ने कार्यकताओं से तिरंगा यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने का आ'ान किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है तथा इसके सम्मान के लिए सभी कार्यकताओं को बिना किसी भेदभाव के अभियान को सफल बनाना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, सभी कार्यकताओं को एकजुट होकर भाजपा की विजय सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना होगा। कार्यशाला में जिला महामंत्री महादेव गाईन, अनुराग अग्निहोत्री, नगर पालिका परिषद पीलीभीत की चेयरमैन डॉ. आस्था अग्रवाल, बरखेड़ा नगर पंचायत चेयरमैन श्याम बिहारी भोजवाल, ब्लॉक प्रमुख निशान सिंह, अशोक शर्मा सहित पार्टी के विभिन्न मोर्चों के जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सरकारी संपत्तियां बचाओ के नारे के साथ हिन्दू महासभा का धरना, जांच की मांग

कार्रवाई न हुई तो जनआंदोलन की चेतावनी

वेलकम इंडिया संवाददाता

पीलीभीत। जनपद में सरकारी तालाबों, ग्राम समाज भूमि, नजूल भूमि, शत्रु संपत्तियों, खेल मैदानों, धोबी घाटों और श्मशान भूमि पर कथित अवैध कब्जों के विरोध में मंगलवार को अखिल भारत हिन्दू महासभा ने सदर तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष पं. पंकज शर्मा के नेतृत्व में आयोजित धरने में संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकताओं ने प्रशासन पर सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उप डीएम को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने और दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई।धरने को संबोधित करते हुए पं. पंकज शर्मा ने कहा कि सरकारी तालाबों, ग्राम समाज भूमि और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन लगातार शिकायतों और दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद अधिकांश मामलों में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के छोटे अतिक्रमण पर तत्काल कार्रवाई होती है, जबकि प्रभावशाली लोगों द्वारा सरकारी जमीनों पर कथित कब्जों के मामलों में फाइलें वर्षों तक लंबित रहती हैं। उन्होंने पकड़िया नौगवां एतमाली स्थित वसुंधरा कॉलोनी का उल्लेख करते हुए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो संबंधित भूमाफियाओं, कॉलोनाइजरों तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की।संगठन ने चंदोई क्षेत्र के तालाब, खेल मैदान और धोबी घाटों पर कथित अतिक्रमण, चिड़ियादाह समेत विभिन्न गांवों की श्मशान भूमि पर कब्जों तथा नकटादाना सहित शत्रु संपत्तियों की जांच का मुद्दा भी उठाया।

धनपति वर्मा का भाजपा सरकार पर तीखा हमला, बोले महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ी, गांवों की बदहाली ने खोली विकास के दावों की पोल

वेलकम इंडिया संवाददाता

पीलीभीत। समाजवादी अधिवक्ता सभा के 128 विधानसभा बरखेड़ा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता धनपति वर्मा एडवोकेट ने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, ग्रामीण विकास तथा कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के खोखले दावे और प्रचार की राजनीति में व्यस्त है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि गांवों में आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। धनपति वर्मा ने कहा कि महंगाई

लगातार बढ़ रही है और आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों और युवाओं से किए वादों को पूरा करने के बजाय केवल बड़े-बड़े दावों और विज्ञापनों के जरिए जनता को गुमराह करने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल और विकास कार्यों की स्थिति सरकार के दावों की असली तस्वीर सामने ला रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं आज भी जस की तस हैं और जिम्मेदार अधिकारी जनता की शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध की घटनाओं के कारण आम नागरिकों में असुरक्षा का माहौल है। सरकार को प्रचार और राजनीति से बाहर निकलकर जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

जनसंपर्क अभियान के दौरान धनपति वर्मा ने गंगापुरी, डंडिया रांझे, बरगदा, फूटाकुंआ ता. कुरैया, खगाई, लखनऊ गौटिया, अमखेड़ा लखनऊ, भगवन्तापुर, काजल खोजी और मधुपुरी समेत कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा।धनपति वर्मा ने कार्यकताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और गांव-गांव जाकर जनता से जुड़ने का आ'ान किया। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पूरी ताकत से उठाया जाएगा और आने वाले समय में भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस दौरान डॉ. ऋषिपाल वर्मा, कामता प्रसाद, राजीव कुमार वर्मा, सतीश कुमार वर्मा, वीर प्रताप सिंह, सुरेश चंद्र, सेवाराम, जगदीश लोधी, शोभित, वेद प्रकाश दीक्षित, शंकर लाल, अरमान अली, अरविंद राजपूत, प्रशांत कुमार गंगवार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

सपा नेता ने सावन में कांवड़ियों का फूल-मालाओं से स्वागत

वेलकम इंडिया संवाददाता

पीलीभीत। सावन महापर्व के अवसर पर कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा पर रवाना हो रहे शिवभक्तों का 127 विधानसभा पीलीभीत क्षेत्र में फूल-मालाओं से स्वागत एवं सम्मान किया गया। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सतेंद्र मौर्य ने कांवड़ियों का फूल- मालाओं से स्वागत करते हुए उनके मंगलमय यात्रा की कामना की।बताया गया कि क्षेत्र के कांवड़ियों का जत्था अपने ग्राम से कच्छला घाट के लिए रवाना हुआ। कांवड़िये कच्छला घाट से गंगाजल लेकर वापस लौटेंगे और इसके बाद गौरीशंकर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर ग्रामीणों में भी खासा उत्साह नजर आया। कांवड़ियों की रवानगी के दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे और उन्होंने शिवभक्तों का उत्साहवर्धन किया।इस

अवसर पर गांव के प्रमुख एवं सम्मानित लोगों में तिलक राम वर्मा और महंत उमाशंकर वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दर्जनों कांवड़ियों के स्वागत के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की।सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सतेंद्र मौर्य ने कहा कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और आस्था का पर्व है। कांवड़ यात्रा में शामिल शिवभक्तों का स्वागत एवं सम्मान करना श्रद्धा और सेवा का कार्य है। उन्होंने सभी कांवड़ियों की यात्रा मंगलमय होने की कामना की। कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के नगर उपाध्यक्ष अशोक सैनी, देवकुमार मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कांवड़ियों की रवानगी के दौरान गांव में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा।

इस दौरान शिवभक्तों के लिए पेयजल, शीतल पेय एवं प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई। ग्रामीणों ने 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ कांवड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण और धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहा।

9 से 17 अगस्त तक चलेगा 'हर घर तिरंगा' अभियान, तैयारी में जुटा प्रशासन

डीएम आलोक कुमार ने की तैयारियों की समीक्षा, 'वंदे मातरम' के सामूहिक गायन, तिरंगा रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट और शहीद स्मारकों के सौंदर्यीकरण के दिए निर्देश

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। आगामी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को जनपद में पूरे उत्साह, गरिमा और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाने के लिए जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े सभी कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सत्य प्रकाश, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चंद्रेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद के सभी शहीद स्मारकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की विशेष साफ-सफाई, रंगाई-पुताई और आसपास के मार्गों को व्यवस्थित कराया जाए। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने के कार्यक्रम भी गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित किए जाएं। जिलाधिकारी ने शासन के निदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक पूरे जनपद में 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने कार्यालयों और घरों पर तिरंगा फहराने तथा आम नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने जनपदवासियों से भी आग्रह किया कि वे अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर पूरे सम्मान और देशभक्ति की भावना के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराते समय राष्ट्रीय ध्वज संहिता का पूर्ण पालन किया जाए। तिरंगा साफ-सुथरा, बिना किसी क्षति के तथा निर्धारित 3:2 अनुपात में होना चाहिए। ध्वज फहराते समय सबसे ऊपर केसरिया, बीच में अशोक चक्र सहित सफेद तथा सबसे नीचे हरा रंग होना चाहिए। अभियान समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारकर सुरक्षित रखा जाए। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। तय कार्यक्रम के अनुसार 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जनपदभर में प्रभात फेरी एवं प्रार्थना सभाओं का आयोजन होगा। इसके बाद प्रातः 8 बजे सभी सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों, तहसीलों, विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज में गुलाब की पंखुड़ियां बांधकर उसे फहराने की भी व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष शासन के निदेर्शानुसार ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का भी सामूहिक गायन कराया जाएगा। साथ ही सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाएंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सूर्यास्त से पहले राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक में 12 अगस्त को विकास भवन परिसर से मौलाना आजाद इंटर कॉलेज तक भव्य तिरंगा रैली तथा 13 अगस्त को जिला सैनिक कल्याण भवन में तिरंगा कॉन्सर्ट आयोजित करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डीसी एनआरएलएम तथा शहरी क्षेत्रों में डूडा को सौंपी गई। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के सभी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षकों और विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत, भाषण, निबंध, चित्रकला एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए। उन्होंने नागरिकों से ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की। मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की मिनट-टू-मिनट कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों की जानकारी दी और सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराने का भरोसा दिलाया। बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमर राय, जिला महामंत्री हैप्पी राय, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रामानुज कनौजिया, प्रभागीय वनाधिकारी हरिकेश यादव, जिला विकास अधिकारी, डीसी एनआरएलएम प्रवीण शुक्ला, जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार, जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.के. तिवारी, डिप्टी आरएमओ कमलेश कुमार, एसडीओ विद्युत के.एन. शुक्ला, जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अवधेश भारती, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा सतीश कुमार, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

आवारा गोवंश के हमले में महिला घायल, गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर

वेलकम इंडिया संवाददाता

कांधला। कस्बे के मोहल्ला मिर्दगान में एक आवारा गोवंश ने सड़क किनारे खड़ी महिला पर हमला कर दिया। टक्कर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने घायल महिला को उपचार के लिए नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लोगों ने आवारा गोवंशों को पकड़कर गौशाला भेजने की मांग की है।

कस्बे के मोहल्ला मिर्दगान निवासी महिला इमराना पत्नी शकीर मंगलवार को अपने घर के बाहर सड़क किनारे खड़ी थीं। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक आवारा गोवंश ने अचानक उस पर हमला कर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। गोवंश के हमले के बाद घायल हुई महिला की चीख-पुकार सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास के लोगों ने घायल महिला को नगर के सरकारी अस्पताल मैं उपचार के लिए भर्ती कराया या जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। कस्बे के लोगों का कहना है कि नगर में आवारा गोवंशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे पहले भी कई लोग इनके हमलों में घायल हो चुके हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने मांग की है कि सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंशों को तत्काल पकड़कर अस्थायी गौशाला भेजा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

मोनू हत्याकांड के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग परिजन पहुंचे थाने, सुरक्षा की लगाई गुहार

मोहसीन रहमानी संवाददाता

कांधला। थाना क्षेत्र के गांव नाला में हुए चर्चित कबड्डी खिलाड़ी मोनू हत्याकांड में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मृतक के परिजन थाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी निरीक्षक से मुलाकात कर शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी गुहार लगाई। थाना क्षेत्र में कई दिन पूर्व गांव नाला के निकट ककड़ीपुर मार्ग स्थित रजवाहे के पास बागपत जनपद के गांव ककड़ीपुर निवासी 22 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी मोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद आरोपियों ने शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया था।इस सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी कार्तिक और देशपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपी अब भी फरार हैं।पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि मोनू का अपनी ही गांव की एक युवती से प्रेम-प्रसंग था। युवती के परिजनों ने कई बार दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन संबंध समाप्त नहीं होने पर युवती के चचेरे भाई कार्तिक ने अपने साथियों गांव नाला निवासी अर्जुन, भारसी निवासी सत्यम तथा युवती के पिता देशपाल के साथ मिलकर कथित रूप से सुनियोजित तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।मृतक के पिता सुरेंद्र ने बताया कि घटना के बाद दर्ज मुकदमे में दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन अन्य नामजद आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने आशंका जताई कि फरार आरोपियों से परिवार को खतरा बना हुआ है। इसलिए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी के साथ-साथ परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस जांच के दौरान एक अन्य युवक का नाम भी सामने आया है।

ऑडियो वायरल, सिपाही निलंबित, मुकदमा दर्ज कराने की मांग

मोहसीन रहमानी संवाददाता

कांधला। थाना पुलिस एक बार फिर चचाओं में है। कस्बे के एक व्यापारी को कथित रूप से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले सिपाही का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक शामली ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि, पीड़ित व्यापारी का कहना है कि केवल निलंबित करने से न्याय नहीं मिलेगा। उसने आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।कस्बा निवासी सचिन, जो दिल्ली बस अड्डे के पास हलवाई की दुकान संचालित करते हैं, ने आरोप लगाया कि थाने में तैनात सिपाही अजय पूनिया कई दिनों से उनकी दुकान पर आकर अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करता था। विरोध करने और उच्चाधिकारियों से शिकायत किए जाने के बाद आरोपी सिपाही ने फोन पर भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की

धमकी दी।पीड़ित व्यापारी ने सिपाही की कथित बातचीत का ऑडियो लगातार दो दिनों तक सोशल मीडिया पर वायरल कर कार्रवाई की मांग की। मामला सामने आने पर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक शामली एन.पी. सिंह ने वायरल ऑडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।इसके बावजूद व्यापारी ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को शिकायत भेजकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कराने तथा आरोपी सिपाही के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि वायरल ऑडियो के आधार पर संबंधित सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत के बाद भी नहीं सुधरी एलईडी लाइट, युवक ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो

वेलकम इंडिया संवाददाता

कांधला। कस्बे के मोहल्ला मौलानान में एक धार्मिक स्थल के निकट लगी नगर पालिका की एलईडी स्ट्रीट लाइट लंबे समय से खराब पड़ी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया।मंगलवार को मोहल्ला मौलानान निवासी भूरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी संबंधित कर्मचारी नदीम ने खराब पड़ी एलईडी लाइट को ठीक नहीं कराया। इससे रात के समय क्षेत्र में अंधेरा रहने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।वीडियो के माध्यम से युवक ने नगर पालिका प्रशासन से जल्द से जल्द खराब एलईडी लाइट को ठीक कराने और क्षेत्र की समस्या का समाधान कराने

की मांग की है। वहीं, वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद स्थानीय लोगों में भी नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

कांग्रेस सोशल मीडिया पदाधिकारियों को मिला मनोनयन पत्र

संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर प्रवीण चंद्र पांडेय ने दिया जोर

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। जिला कांग्रेस कमेटी (सोशल मीडिया विभाग) की नवगठित जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का मंगलवार को खलीलाबाद के गोला बाजार स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों को कांग्रेस का पटका पहनाकर मनोनयन पत्र प्रदान किए गए।

जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद्र पांडेय ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने में सोशल मीडिया विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने नव नियुक्त पदाधिकारियों से पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ संगठन को मजबूत करने का आग्रह किया।विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने सोशल मीडिया को वर्तमान समय में जनता से संवाद का सबसे सशक्त माध्यम बताया। जिला

सचिव अतीक सिद्दीकी ने सभी कार्यकताओं से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आ'ान किया। जिला सोशल मीडिया विभाग के जनपद अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अख्तर ने नवगठित कार्यकारिणी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला उपाध्यक्ष के रूप में सत्या त्रिपाठी, रजनीश कुमार, अमित कुमार सिंह और रेहान परवेज खान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महासचिव पद पर संतोष यादव, सचिन कुमार, मो. इब्राहिम सिद्दीकी और मंजू त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। वहीं, सचिव पद पर चन्द्रकान्त मणि पाण्डेय, देवदत्त मणि त्रिपाठी, अर्पण श्रीवास्तव, ध्रुव कन्नौजिया एवं मुकेश भारती को मनोनीत किया गया है। ब्लॉक अध्यक्षों में सेमरियावां से नूर आलम सिद्दीकी, खलीलाबाद से सच्चिदानंद यादव, सांथा से आफताब आलम, बेलहर कला से विजय पाण्डेय, मेंहदावल से मनभावती, बघौली से बलवंत निषाद, पौली से महेन्द्र कुमार, नाथनगर से मोहन तथा हैंसर से दुर्गेश सैनी को जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा कोऑर्डिनेटर के रूप में 312 मेंहदावल से रामसरन सिंह, 313 खलीलाबाद से अखलाक अहमद चौधरी तथा 314 धनघटा से दिग्विजय नाथ दूबे को मनोनीत किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 313 खलीलाबाद से मोहम्मद सलमान और 312 मेहदावल से ललिता सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, अख्तर हुसैन को विधानसभा महासचिव (खलीलाबाद) तथा सुजाउल्लाह को विधानसभा उपाध्यक्ष (खलीलाबाद) बनाया गया है। इस कार्यक्रम में अरुण पांडेय, राजीव गोंड, मदन दास, रियाज प्रधान, गुड्डू उपाध्याय, अदनान सहित कई अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप पर अभद्र टिप्पणी से समर्थकों में रोष, कार्रवाई की मांग

वेलकम इंडिया/विजय द्विवेदी

प्रतापगढ़। सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह एवं 249 पट्टी विधानसभा से जुड़े एक राजनीतिक पोस्ट पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार, राजा सिंह नामक फेसबुक यूजर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, 249 में कुछ भी कर लो, राम सिंह पटेल ही जीतेंगे, लिख कर ले लो।₹ इस पोस्ट पर अनूप सिंह नामक यूजर ने कथित रूप से अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बताया जा रहा है कि टिप्पणी सामने आने के बाद पूर्व मंत्री के समर्थकों में रोष व्याप्त है। समर्थकों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपनी राजनीतिक राय रखने का अधिकार है, लेकिन असहमति व्यक्त करने के नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है।

समर्थकों ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं, इस मामले को लेकर संबंधित पक्ष की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया या पुलिस में शिकायत दर्ज होने की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है।

नोटः यह समाचार सोशल मीडिया पर उपलब्ध पोस्ट और टिप्पणी के आधार पर तैयार किया गया है। अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के आरोपों या कथनों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यदि इस संबंध में पुलिस शिकायत या आधिकारिक कार्रवाई होती है, तो समाचार को उसी अनुसार अद्यतन किया जा सकता है।

चाय के चुस्की पर जुटे प्रधान, की महापंचायत, गांव के विकास में रोड़ा बने दिक्कतों के खिलाफ सेमरियावां में उठी जोरदार आवाज

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। विकासखंड सेमरियावां के कांटे बाजार में मंगल के दिन आयोजित 'चाय पर चर्चा' कार्यक्रम गांव के विकास, पंचायत के सम्मान और प्रधानों के अधिकार को लेकर ऐतिहासिक बैठक साबित हुई। चाय के चुस्की के बीच ब्लॉक के 113 ग्राम पंचायतन के प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि एक मंच पर जुटे और गांव के विकास में आ रही दिक्कतो पर खुल कर अपनी बात रखी। पूरा माहौल एकजुटता, भाईचारा और पंचायतो के हक के लड़ाई के संकल्प से गूंजता रहा। बैठक के अगुवाई करते हुए युवा प्रधान प्रतिनिधि विकास चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायत गांव के विकास के सबसे मजबूत आधार है, लेकिन लगातार विकास योजनाओं में बाधा, सचिव के क्लस्टर व्यवस्था, भुगतान में देरी और

प्रधानों को अनावश्यक परेशान करने से गांव के विकास प्रभावित हो रहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानों के सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पंचायतो के हक के लिए संगठन हमेशा लोकतांत्रिक तरीका से संघर्ष करेगा और हर समस्या प्रशासन के सामने मजबूती से रखा जायेगा। विकास चौधरी ने कहा कि जब तक गांव के चुने गये जनप्रतिनिधि के सम्मान न मिली, तब तक गांव के समुचित विकास संभव नहीं। उनकर संबोधन पर मौजूद प्रधानो ने जोरदार तालियों से समर्थन जताया। बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष इनामुल्लाह कुरैशी को प्रशासक ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर विकास चौधरी ने माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया और कहा कि अनुभवी नेतृत्व व युवा सोच के साथ संगठन को और मजबूत बनाया जायेगा। वरिष्ठ प्रधान प्रतिनिधि शेषनाथ यादव कहा कि आज के समय में सबसे जरूरी प्रधानों की एकजुटता है। उन्होंने कहा कि विकास चौधरी के नेतृत्व में जो एकता दिखी वह सेमरियावां ब्लॉक के लिए नया संदेश है। अब पंचायतों की आवाज अब पहले कहीं अधिक मजबूती से उठेगी।

प्रधान प्रतिनिधि योगेंद्र जायसवाल ने कहा कि मजबूत पंचायते मजबूत गांव की पहचान हैं। इ एकजुटता से गांव के विकास को नया रफ्तार मिलेगी और पंचायतों के अधिकार की लड़ाई और मजबूती से लड़ी जायेगी। बैठक में प्रदीप पांडेय विकास कार्यों के भुगतान समय से करे, प्रशासनिक बाधा दूर करे और पंचायतो के अधिकार सुनिश्चित करे के मांग उठाया। अमित पटेल ने कहा कि संगठन के मजबूती ही प्रधानों की असली ताकत है। अगर सभी प्रधान एकजुट रहे तो गांव के विकास के रफ्तार कोई नही रोक सकता।

इस अवसर पर शेषनाथ यादव, इसरार अहमद, इरशाद अहमद, अमित पटेल, प्रदीप पांडे, योगेंद्र जायसवाल, लालू सिंह यादव, विनय सिंह, कल्लीमुल्लाह, महफूज अहमद, रमजान अली, अर्जुन प्रसाद, जमालुद्दीन, बैजनाथ चौधरी, स्नेहलता चौधरी, नरेंद्र कुमार, फिरोज अख्तर, हबीबुर्रहमान खान, ताजुद्दीन, अब्दुल हकीम, प्रेमनाथ उर्फ गुड्डू चौधरी, मुनीर अहमद, अबू बकर चौधरी, रामसागर चौधरी, सुलेमान चौधरी, सईद अहमद, रामवृक्ष, प्रदीप चौधरी, गोविंद कुमार, अनुराग, रामानुज तिवारी, रामजी चौधरी, शिवराम समेत भारी संख्या में प्रधान आदि प्रधान प्रतिनिधि मौजूद रहे।

मानकों पर खरे नहीं उतरे 10 आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पताल, जिलाधिकारी ने कार्रवाई का दिया निर्देश

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जनपद में इम्पैनल्ड निजी अस्पतालों की गुणवत्ता, सेवाओं और निर्धारित मानकों की समीक्षा की। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर 10 अस्पतालों की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित टीम ने वर्ष 2018 से 2024 तक आयुष्मान योजना के तहत इम्पैनल किए गए अस्पतालों का निरीक्षण किया। जांच में कई अस्पताल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। कुछ अस्पतालों में बिना वैध पंजीकरण के संचालन, चिकित्सकों की अनुपलब्धता, प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी पाई गई, जिन

अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, उनमें सेहर मेमोरियल हॉस्पिटल (निघुरी बाजार), न्यू केयर हॉस्पिटल (मेंहदावल बाईपास), न्यू मेडविन हॉस्पिटल (गोरखर देहात), मुनमुन क्लीनिक एंड मेटरनिटी हॉस्पिटल (बंगला ताल चौराहा), बालाजी हॉस्पिटल (बाईपास खलीलाबाद), जीवन रेखा हॉस्पिटल (बौर-ब्यास, मेंहदावल), सन्स हॉस्पिटल (टेमा रहमत), एम. गोल्ड हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल (समय माता मंदिर के पीछे, खलीलाबाद) तथा ओम साई हॉस्पिटल (जिला अस्पताल के निकट) शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामानुज कनौजिया ने बताया कि आयुष्मान योजना में इम्पैनल 37 अस्पतालों में से चार को अब तक कोई दावा भुगतान नहीं हुआ है। जबकि शेष 33 अस्पतालों में रजत हॉस्पिटल, एसआर हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल, शम्भूनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल, पटेल हॉस्पिटल और स्पर्श हॉस्पिटल को सर्वाधिक दावे एवं भुगतान प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने इन अस्पतालों के दावों और भुगतान की पुनः जांच अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम से कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर के लिए डी-फाइब्रिलेटर, फायर सेफ्टी व्यवस्था तथा कम से कम दो आपात निकास (इमरजेंसी एग्जिट) दो सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

रेलवे सुरक्षा अभियान में वाराणसी जीआरपी को मिली बड़ी सफलता, चोरी के मामले का वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

न्यायालय से जारी वारंट पर जीआरपी की कार्रवाई, लंबे समय से फरार आरोपी को दबोचा

वेलकम इंडिया/संतोष कुमार सिंह

वाराणसी। रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों एवं सरकुलेटिंग एरिया में चोरी की घटनाओं की रोकथाम, अपराधियों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी, अवैध तस्करी पर प्रभावी अंकुश तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जीआरपी वाराणसी को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर कार्रवाई करते हुए जीआरपी ने चोरी के मामले में वांछित एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी., पुलिस महानिरीक्षक एन. कोलान्ची, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग प्रयागराज प्रशांत वर्मा तथा पुलिस उपाधीक्षक रेलवे वाराणसी कुँवर प्रभात सिंह के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक जीआरपी कैंट वाराणसी रजोल नागर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उपनिरीक्षक श्रीकांत यादव (प्रभारी चौकी जीआरपी काशी) एवं कांस्टेबल श्रीकांत यादव ने कार्रवाई करते हुए अमानु उर्फ अमन उर्फ अमानुर्रहमान पुत्र अनीसुर्रहमान, निवासी ए-31/38 सीए, नवापुरा, हनुमान फाटक, थाना आदमपुर, वाराणसी (उम्र लगभग 26 वर्ष) को उसके आवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त न्यायालय एसीजेएम (एनआर), वाराणसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट (धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत मुकदमा संख्या 307/2022, धारा 379/411 भारतीय दंड संहिता, थाना जीआरपी कैंट, वाराणसी का वारंटी था। पुलिस टीम ने न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए 3 अगस्त 2026 (सोमवार) को उसे विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया तथा थाना जीआरपी कैंट लाकर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के बाद न्यायालय में पेश कर दिया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रजोल नागर, उपनिरीक्षक श्रीकांत यादव (प्रभारी चौकी जीआरपी काशी) एवं कांस्टेबल श्रीकांत यादव शामिल रहे। जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

आज फिर पड़ा मौसम का प्रभाव जनसुनवाई पर

केवल पांच समस्याएं पहुंची, एक का हुआ तत्काल निस्तारण

वेलकम इंडिया संवाददाता

सहारनपुर। आज फिर मौसम का प्रभाव नगर निगम में जनसुनवाई पर पड़ा। आज केवल पांच समस्याएं आयी, जिनमें से एक समस्या का तत्काल निस्तारण करा दिया गया। शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वार्ड 58 लोहा बाजार निवासी नवीन ने लोहा बाजार में मंदिर की जमीन पर किये गए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर अपर नगरायुक्त ने प्रवर्तन दल प्रभारी को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वार्ड 02 सोनिया विहार निवासी प्रमोद सैनी ने गली नंबर आठ में नाली की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अपर नगरायुक्त प्रदीप यादव ने तुरंत क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक व सफाई मित्र को भेजकर सफाई कराते हुए समस्या का समाधान करा दिया। वार्ड 58 गालिब रसूल चंडीगढ़ पैलेस निवासी बिलाल अहमद ने गटर की सफाई व पानी की लीकेज ठीक कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिए। जिस पर अवर अभियंता जल को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा वार्ड 27 हरदेव नगर माता गदानंद मंदिर निवासी पवन ने मंदिर में बंद पडे. सबमर्सिबल को चालू कराने के लिए प्रार्थना दिया। जनसुनवाई में मुख्य अभियंता निर्माण सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण शाह सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अलीपुर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, नीरज बवाना-नवीन बाली गैंग का सक्रिय बदमाश गिरफ्तार

वेलकम इंडिया/एहसान अंसारी

नई दिल्ली। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में देर रात पुलिस और एक कुख्यात गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें नीरज बवाना-नवीन बाली गैंग का सक्रिय सदस्य सविंदर उर्फ बाबा उर्फ पागल पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त की रात करीब 10 बजे स्पेशल स्टाफ और थाना अलीपुर की संयुक्त टीम को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश सविंदर उर्फ बाबा उर्फ पागल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जीटीके रोड से हिरणकी पुश्ता रोड की ओर आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर ट्रैप लगाया। जैसे ही पुलिस टीम ने आरोपी को रुकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, उसने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सब-इंस्पेक्टर विशाल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जिससे उनकी जान बाल-बाल बच गई। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। मुठभेड़ में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। घायल बदमाश को पहले राजा हरिश्चंद्र अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, तीन खोखा कारतूस (7.65 एमएम) और दो खोखा कारतूस (9 एमएम) बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, सविंदर उर्फ बाबा उर्फ पागल, गांव सनोथ, नरेला का रहने वाला है और उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट समेत छह आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह अलीपुर और नरेला क्षेत्र में व्यापारियों और प्रॉपर्टी डीलरों से उगाही कर दहशत फैलाने का काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नीरज बवाना-नवीन बाली गैंग के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार है। मामले में आगे की जांच जारी है।

बाइक चोरी के दो मामलों का नहीं लगा सुराग, पीड़ितों ने डीआईजी से लगाई गुहार

कांधला। थाना क्षेत्र के गांव इस्सोपुरटील में बाइक चोरी के दो मामलों का पुलिस करीब एक माह बाद भी खुलासा नहीं कर सकी है। पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद न तो उनकी बाइक बरामद की गई और न ही मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों ने डीआईजी सहारनपुर से कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र के गांव इस्सोपुरटील निवासी रजनीश ने बताया कि विगत 1 जुलाई को वह गांव के शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करने गया था। इस दौरान उसने अपनी बाइक मंदिर के बाहर खड़ी की थी, जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। घटना की सूचना तत्काल डायल-112 और थाना पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार 21 जुलाई को गांव निवासी दीपक पुत्र प्रीतम की भी शिव मंदिर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन उसका आरोप है कि न तो बाइक बरामद की गई और न ही मुकदमा दर्ज किया गया।

काशी के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य त्रिवेणी प्रसाद शुक्ल के पिता पं. उमाशंकर शुक्ल को भावभीनी श्रद्धांजलि

95 वर्षीय पं. उमाशंकर शुक्ल के निधन पर शोकसभा आयोजित, साहित्यकारों व गणमान्यों ने उनके सरल, मृदुभाषी और समाजसेवी व्यक्तित्व को किया नमन

वेलकम इंडिया/संतोष कुमार सिंह

वाराणसी। काशी के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य एवं दिव्य दर्शन ज्योतिष केंद्र के संस्थापक आचार्य त्रिवेणी प्रसाद शुक्ल के पिता पंडित उमाशंकर शुक्ल के निधन पर अखिल भारतीय लेखक, कवि एवं कलाकार परिषद की ओर से सुदामा फाउंडेशन, चितईपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन परिषद के संस्थापक कवि इंद्रजीत तिवारी 'निर्भीक' ने किया, जबकि अध्यक्षता डॉ. राजीव गौतम ने की।

श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने पंडित उमाशंकर शुक्ल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए उन्हें सरल, मृदुभाषी, स्पष्टवादी तथा समाजसेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि 95 वर्ष की आयु तक उन्होंने अनुशासित और आध्यात्मिक जीवन जिया। योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के प्रति उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके संतुलित एवं प्रेरणादायी जीवन का आधार रही।

बताया गया कि पंडित उमाशंकर शुक्ल पिछले कुछ समय से श्वास संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। विगत तीन दिनों से उनका उपचार वाराणसी के सिगरा स्थित मिडवे अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

पंडित उमाशंकर शुक्ल मूल रूप से भदोही जनपद के मऊरामशाला मतेथू गांव के निवासी थे तथा वाराणसी के चांदपुर क्षेत्र में भी उनका आवास था। उनके चार पुत्र हैं– प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य त्रिवेणी प्रसाद शुक्ल, पूर्व प्रधान जगदंबा प्रसाद शुक्ल, कड़ेदिन शुक्ल तथा बैंक अधिकारी नागेश शुक्ल। परिवार के साथ-साथ समाज में भी उनका विशेष सम्मान था। श्रद्धांजलि सभा में कर्नल रणजीत उपाध्याय, पं. गंगा सहाय पांडेय, पं. कमलकांत उपाध्याय, कवि इंद्रजीत तिवारी 'निर्भीक', संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक द्विवेदी 'गणेश', धनंजय पांडेय 'धन्नू बाबा', अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, डॉ. महेंद्र तिवारी 'अलंकार', डॉ. गिरीश पांडेय 'काशिकेय', डॉ. धर्मदेव यादव 'धर्मेश', कवि बुद्धदेव तिवारी सहित अनेक साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य नागरिकों ने पंडित उमाशंकर शुक्ल को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

कांवड़ यात्रा की तैयारियों का डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा

वेलकम इंडिया संवाददाता

मेरठ। कांवड़ यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को मेरठ के बहसूमा स्थित सिद्ध पीठ फिरोजपुर महादेव मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे और मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने मंदिर परिसर और कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर, कांवड़ मार्ग, प्रवेश और निकास व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता तथा पेयजल की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। एसएसपी अविनाश पांडे ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा की कामना की। मंदिर परिसर स्थित महर्षि दुवार्सा की तपोस्थली से जुड़े पौराणिक तालाब की जर्जर स्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तालाब की तत्काल सफाई, सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके संरक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मंदिर समिति के प्रतिनिधि हरजिंदर सिंह ने श्रद्धालुओं के लिए नए हैंडपंप लगाने की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि नई हैंडपंप योजना बंद हो चुकी है। हालांकि ब्लॉक में उपलब्ध पुराने स्पेयर हैंडपंप को री-बोर कराकर मंदिर परिसर के पास स्थापित कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को पेयजल की सुविधा मिल सके।

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्र संघों के चुनाव तत्काल कराए जाएं: मो0 अरशद खान

वेलकम इंडिया संवाददाता

जौनपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक जौनपुर सदर मोहम्मद अरशद खान ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों एवं इंटर कॉलेजों में लंबे समय से बंद पड़े छात्र संघ चुनावों को तत्काल बहाल कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से चुनाव कराए जाएँ।

उन्होंने कहा कि छात्र संघ लोकतंत्र की पहली पाठशाला हैं। देश के अनेक महान नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक नेतृत्व छात्र राजनीति से निकलकर ही राष्ट्रीय जीवन में अपनी पहचान बना सके हैं। छात्र संघ केवल चुनाव का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक मूल्यों, अनुशासन, संगठन क्षमता तथा जनसेवा की भावना विकसित करने का सबसे सशक्त मंच हैं। उन्होंने ने कहा कि जब शिक्षण संस्थानों में छात्र प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाता है, तब विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान का कोई प्रभावी मंच नहीं बचता। छात्र संघ शिक्षा व्यवस्था, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल, छात्रवृत्ति, सुरक्षा, परिवहन, रोजगार मार्गदर्शन तथा अन्य छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक ढंग से प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इससे टकराव के बजाय संवाद की संस्कृति विकसित होती है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, देश का भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा। छात्र संघ चुनाव युवाओं को संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं, मतदान की महत्ता और जिम्मेदार नेतृत्व का व्यावहारिक प्रशिक्षण देते हैं। यही विद्यार्थी आगे चलकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में छात्र संघ चुनावों का नियमित आयोजन युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, शिक्षा संस्थानों में सकारात्मक वातावरण बनाएगा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सभी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और इंटर कॉलेजों में शीघ्र छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा की जाए, ताकि प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को अपना लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हो सके। अंत में उन्होंने कहा कि ₹जिस प्रदेश का युवा जागरूक, शिक्षित और लोकतांत्रिक होगा, वही प्रदेश विकास, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय प्रगति में अग्रणी बनेगा। छात्र संघ चुनाव युवाओं के अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती की भी अनिवार्य आवश्यकता हैं।

सेमरियावां ब्लॉक परिसर के बाहर अवैध अतिक्रमण पर बीडीओ का सख्त रुख

दुकानदारों को अंतिम चेतावनी, अतिक्रमण नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई; एसडीएम और सीओ को भेजा जाएगा पत्र

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। सेमरियावां विकास खंड कार्यालय के बाहर फैले अवैध अतिक्रमण और गंदगी को लेकर खंड विकास अधिकारी कृष्ण कुमार दूबे ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्लॉक परिसर के बाहर किए गए अतिक्रमण और अव्यवस्था पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दी।

खंड विकास अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को तत्काल स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि चेतावनी के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं क्षेत्राधिकारी (सीओ) को पत्र भेजकर संयुक्त अभियान चलाने का अनुरोध किया जाएगा, ताकि ब्लॉक परिसर के बाहर अतिक्रमण मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। बीडीओ कृष्ण कुमार दूबे ने कहा कि सरकारी कार्यालयों के आसपास स्वच्छता बनाए रखना और आमजन के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न हो, यह प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी दुकानदारों से सहयोग की अपील करते हुए स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का आग्रह किया।

रोहिणी साउथ थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर सिंह के तबादले पर समाजसेवियों ने दी विदाई, सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की गई कामना

वेलकम इंडिया/एहसान अंसारी

नई दिल्ली। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के आने के बाद कई पुलिस थाने एसएचओ का तबादला किया गया है। ऐसे में रोहिणी साउथ थाने के एसएचओ ज्ञानेश्वर सिंह के ताबदले की सूचना मिलते ही इलाके के गड़मान्य लोग उनसे मिलने थाने मेँ पहुंचे। इसी कड़ी में भोजपुरी सेवा समिति के पदाधिकारी भी थाना अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह से मिलने पहुंचे। ज्ञानेश्वर सिंह नें आये हुए अतिथियों का हिर्दय से स्वागत किया। भोजपुरी सेवा समिति के अध्यक्ष मनोज सिंह नें थाना अध्यक्ष को अंगवस्त्र से सम्मानित किया। हसीना शेख नें तुलसी जी का पौधा भेंट किया। उपाध्यक्ष पंकज भरेजा नें पुष्प गुच्छ भेंट करके उन्हें नई जिम्मेदारी की बधाई दी। मिडिया प्रभारी श्याम बघेल नें गुलदस्ता भेंट कर उनको सम्मानित किया। महासचिव जय करण सिंह नें मिठाई खिला कर उनको नई जिम्मेदारी की बधाई दी। सचिव अमित नें पटका पहना कर उन्हें सम्मानित किया। रोहिणी साऊथ थाने के इलाके में थाना अध्यक्ष नें कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा नागरिकों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई सटीक प्रयास किये।

पुलिसकर्मियों के साथ इलाकों में पैदल गश्त की व्यवस्था अक्सर बहाल रही। इलाके में चोरी झपटमारी की वारदात को काफी हद तक रोकने मेँ सफल भी रहे। पैदल गश्त के दौरान थाना अध्यक्ष ने संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करते रहते थे , स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों से संवाद स्थापित करते थे तथा उनकी समस्याएँ सुनते थे। सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी समय समय पर अपने थाने के पुलिस अधिकारीयों को देते रहते थे।

सिक्योरिटी गार्ड का सिर में गोली लगा शव घर में मिला

मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र की नीलकंठ कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड बालेंद्र कुमार (55) का सिर में गोली लगा शव घर में पड़ा मिला। सोमवार सुबह पत्नी उन्हें खाना देने पहुंची तो घटना की जानकारी हुई। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में सिक्योरिटी गार्ड खून से लथपथ पड़े थे। शव के पास में उनकी लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक पड़ी हुई थी। सूचना पर एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस प्रथम दृष्टयाआत्महत्या का मामला मान रही है। परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। एसपी सिटी ने बताया कि बालेंद्र मूल रूप से बागपत जनपद के बिनौली थाना क्षेत्र के बरनावा गांव के रहने वाले थे। वो 15 वर्ष से अपने परिवार के साथ टीपी नगर थाना क्षेत्र में रह रहे थे। वह एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। बालेंद्र की पत्नी सुनीता अपने बेटे और बेटी के साथ रोहटा रोड स्थित गोकुल विहार में रहते हैं।

हल्की बूंदाबांदी के बीच सुरक्षा के कड़े पहरे में निकला मोहर्रम के चेहल्लुम का जुलूस

वेलकम इंडिया संवाददाता

बिस्कोहर/सिद्धार्थनगर। नगर पंचायत बिस्कोहर में मोहर्रम का चेहल्लुम का मेला पारंपरिक श्रद्धा और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मंगलवार दोपहर हल्की बूंदाबांदी के बीच पश्चिम गणिकाओं के मोहल्ले से ताजियों का जुलूस निकाला गया। कर्बला मैदान में आधा दर्जन से अधिक ताजियों को ठंडा कर अकीदतमंदों ने शीरनी चढ़ाई और मुल्क में अमन-चैन की दुआ मांगी। मंगलवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बिस्कोहर के पश्चिम मोहल्ले में रखे गए ताजियों का जुलूस पारंपरिक रास्तों से होते हुए शाम 5 बजे पश्चिम व दलपतपुर स्थित कर्बला मैदान पहुंचा। यहाँ बने चौक पर फातिहाख्वानी के बाद गमगीन माहौल में ताजियों को ठंडा किया गया। मेले में खरीदारी के लिए दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी रही। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष हरे कृष्ण उपाध्याय और बिस्कोहर चौकी प्रभारी अमित कुमार शाही भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से विक्की, रुमाला, अनीता, रमजानी, पप्पी, पप्पू, मंजू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

राज चौपला स्थित प्रशासनिक कांवड़ शिविर का भव्य उद्घाटन

जनप्रतिनिधियों ने कांवड़ यात्रियों की सेवा व्यवस्था का लिया जायजा

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। राज चौपला, मोदीनगर स्थित प्रशासनिक कांवड़ शिविर का भव्य उद्घाटन माननीय सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष रामपाल चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं कुशल सर्जन डॉ देवेंद्र शिवाच एवं नगर पालिका परिषद मोदीनगर के चेयरमैन विनोद वैशाली की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया तथा कांवड़ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा सहायता, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का महापर्व है तथा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता है। उन्होंने कांवड़ यात्रियों के लिए नगर पालिका एवं प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु, नगर पालिका परिषद मोदीनगर के सभासदगण, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया गया तथा कांवड़ यात्रा के सफल संचालन हेतु सभी के सहयोग की अपेक्षा की गई।

इस मौके पर एस डी एम कोमल पंवार, अधिशासी अधिकारी नरेंद्र मोहन मिश्र, राजस्व निरीक्षक अंकित चौधरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर करण सिंह, सभासद वेद प्रकाश चौधरी सूबे सिंह, राहुल राणा गोल्डी नेहरा किशन राज सेन रजनीश चौधरी ललित मित्तल आदित्य बॉबी मोनू धमा, ललित त्यागी, नीटू चौधरी संजय चौधरी दुष्यंत यादव जितेंद्र चौधरी, अरुण खन्ना, हेमंत पालीवाल, नवीन जायसवाल, दीपक गुज्जर, जयप्रकाश वशिष्ठ, नरेश अमराला, सतेन्द्र तोमर, अमित चौधरी, आकाश शर्मा दौलत राम अनिल सेन अमितेज जैन दीपांशु मलिक सागर गुप्ता गोपाल गौतम अशीष कश्यप सतीश लाल दास मनीष अग्रवाल संजय शर्मा अमित कराटे महेश तायल,पप्पन शर्मा, पिंकी चौधरी, नीरज तेवतिया, जीत सिंह आदि उपस्थित रहे।

निवोक हॉस्पिटल के तृतीय कांवड़ मेडिकल शिविर का शुभारंभ, एसीपी भास्कर वर्मा ने किया उद्घाटन

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित सीकरी गांव में निवोक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल द्वारा आयोजित तृतीय कांवड़ मेडिकल शिविर का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। शिविर का उद्घाटन एसीपी भास्कर वर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमित शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह में एसीपी भास्कर वर्मा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को त्वरित एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सराहनीय पहल है। उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन के इस सामाजिक कार्य की प्रशंसा की। हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमित शर्मा ने बताया कि यह मेडिकल शिविर 11 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। शिविर में सभी प्रकार की आवश्यक दवाइयां, प्राथमिक उपचार, चिकित्सकीय परामर्श सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए तीन एंबुलेंस तथा करीब 30 सदस्यीय मेडिकल स्टाफ 24 घंटे सेवाएं देगा, जिससे कांवड़ यात्रियों को तत्काल उपचार मिल सके।

इस अवसर पर पप्पन शर्मा (सीकरी), राहुल प्रधान (सीकरी), अतुल शर्मा, सचिन शर्मा, शहर कोतवाल आनंद मिश्रा सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। यह मेडिकल शिविर कांवड़ यात्रियों की सुविधा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

पतंजलि वैलनेस सेंटर द्वारा जड़ी बूटी दिवस मनाया,किया यज्ञ-हवन

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। पतंजलि वैलनेस सेंटर मोदीनगर में आचार्य बालकृष्ण के प्राकट्य दिवस के अवसर पर जड़ी बूटी दिवस मनाया गया।इस मौके पर प्रातः यज्ञ-हवन किया गया, भक्ति गीत एवं बच्चों द्वारा संगीतमय योग का कार्यक्रम हुआ, सभी गणमान्य व्यक्ति ने अपने विचार व्यक्त किए। स्वामी आरोग्य देव ने सभी को औषधीय पौधे वृत्त किये। स्वामी आरोग्य देव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए औषधीय पौधे का हमारे जीवन में जो महत्व है बताया। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग पीठ तहसील की टीम द्वारा पौधे रोपे गए। करतार सिंह भाटी सह प्रभारी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग जिला गाजियाबाद द्वारा मंच संचालन करते हुए पूज्य आचार्य बालकृष्ण को नमन करते हुए योग आयुर्वेद में पूज्य के विशेष योगदान अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति ने अपने विचार व्यक्त किए। तहसील मोदीनगर योग परिवार के सभी योग साधकों ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

दिनेश कुमार गोयल सदस्य विधान परिषद द्वारा स्कूली बसों को टोल टैक्स से मुक्त करने व फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने की मांग की

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। ।उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य दिनेश कुमार गोयल एवं विजय बहादुर पाठक ने आज विधान परिषद में नियम-110 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण जनहित के विषय उठाते हुए प्रदेश सरकार का ध्यान आम नागरिकों की सुविधा एवं विद्यार्थियों के हित से जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित किया। पहले विषय में दोनों सदस्यों ने टोल प्लाजा के आसपास स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाली स्कूली बसों को टोल टैक्स से पूर्णतः मुक्त किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कई बार टोल प्लाजा से गुजरने के कारण स्कूल बसों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव विद्यार्थियों के अभिभावकों पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि केवल टोल शुल्क के कारण ही प्रति विद्यार्थी लगभग 800 से 850 प्रतिमाह का अतिरिक्त व्यय आता है, जबकि डीजल, चालक-परिचालक के वेतन, वाहन रखरखाव एवं अन्य खर्चों को जोड़ने पर यह व्यय लगभग 2,000 प्रतिमाह या उससे अधिक हो जाता है। ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से सामान्य परिवारों के लिए यह अतिरिक्त बोझ शिक्षा प्राप्त करने में बाधा बन रहा है।इसलिए अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी स्कूली बसों को टोल टैक्स से पूर्णतः मुक्त किया जाना चाहिए।दोनों सदस्यों ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार इन दोनों महत्वपूर्ण जनहित के विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेशवासियों को राहत प्रदान करेगी। एक ओर अतिक्रमण मुक्त एवं सुरक्षित सार्वजनिक मार्ग उपलब्ध होंगे, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा तथा शिक्षा को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरे विषय में दोनों सदस्यों ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न नगरों, विशेषकर लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर सहित अन्य शहरों में फुटपाथों, सार्वजनिक मार्गों एवं सड़कों पर लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल यात्रियों के लिए बने फुटपाथों पर अवैध पार्किंग, अस्थायी एवं स्थायी कब्जों तथा व्यावसायिक गतिविधियों के चलते महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं स्कूली बच्चों का सुरक्षित आवागमन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय समय-समय पर सार्वजनिक भूमि एवं फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर प्रभावी एवं स्थायी कार्रवाई का अभाव दिखाई देता है। इसलिए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाकर फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, अवैध कब्जों के विरुद्ध नियमित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में पुनः अतिक्रमण न हो और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

गंग नहर पतला पर कांवड़ सेवा शिविर का भव्य उद्घाटन

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। गंग नहर पर कांवड़ सेवा शिविर का गरिमामयी शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस पावन अवसर पर शिव भक्तों की सेवा के लिए आयोजित इस शिविर में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण डॉ. राजकुमार सांगवान (सांसद, बागपत लोकसभा रालोद) चौधरी तेजपाल सिंह (राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, रालोद) बीरपाल मलिक पीआरओ जयंत चौधरी रीता चौधरी (चेयरमैन, नगर पंचायत पतला) अमरजीत सिंह बिड्डी प्रदेश अध्यक्ष (सहकारिता प्रकोष्ठ),अजय प्रमुख (भिकनपुर),राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष रामपाल चौधरी,अरुण उर्फ भुल्लन (जिला संयोजक, गाजियाबाद रालोद) योगेंद्र सिंह (क्षेत्रीय महासचिव, रालोद), रणवीर दहिया (प्रदेश सचिव, रालोद) सुनील रोहटा (प्रदेश प्रवक्ता, रालोद) बिट्टू खंजरपुर (क्षेत्रीय महासचिव गाझ्र बाद) डॉझ्र अनिल मोदीनगर , समस्त नगर पंचायत एवं क्षेत्रवासी अतिथियों ने शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया और कांवड़ यात्रा पर आ रहे शिव भक्तों की सेवा के इस नेक कार्य की सराहना करते हुए सभी को शुभकामनाएं दीं।

सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न कांवड़ सेवा शिविरों में शिवभक्तों की सेवा की

वेलकम इंडिया संवाददाता

मेरठ। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के भोला झाल मार्ग पर संचालित विभिन्न कांवड़ सेवा शिविरों में राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व महासचिव एवं पूर्व विधानसभा प्रभारी रणवीर सिंह दहिया ने अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर शिवभक्तों की सेवा करते हुए उनकी कुशलक्षेम जानी तथा शिविरों की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

शिविर आयोजक विपिन चौधरी (शेखपुरी), एवं अन्य आयोजक सिंचाई विभाग से शिव कांवड़ सेवा शिविर, मुकेश गुप्ता एवं उनके साथियों द्वारा आयोजित शिव कांवड़ सेवा शिविर, तथा ग्राम सतवाई कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचकर शिवभक्तों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया तथा सेवा कार्यों में सहभागिता निभाई।इन शिविरों में प्रतिदिन सैकड़ों शिवभक्त विश्राम कर रहे हैं, जहाँ उन्हें भोजन, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रणवीर सिंह दहिया ने शिविर संचालकों एवं स्वयंसेवकों के सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की निस्वार्थ सेवा भारतीय संस्कृति की महान परंपरा है और शिवभक्तों की सेवा करना अत्यंत पुण्य का कार्य है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सदैव समाज सेवा और जनसेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे तथा कांवड़ सेवा शिविरों के सफल एवं सुचारु संचालन में हरसंभव सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ मोनू ढिंढाला, सत्येंद्र चौधरी (ग्राम बुड्ढा), संदीप चौधरी (मल्लापुर), गौरव चौधरी सहित राष्ट्रीय लोकदल के अनेक कार्यकताओं ने शिवभक्तों को जल, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्रिय सहयोग किया।

रणवीर सिंह दहिया ने सभी शिवभक्तों से अपील की कि वे अपनी कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक, अनुशासन एवं आपसी सौहार्द के साथ पूर्ण करें, यातायात नियमों एवं कानून-व्यवस्था का पालन करें तथा सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं की मंगलमय, सुरक्षित एवं सफल कांवड़ यात्रा की कामना करते हुए सभी सेवा शिविर संचालकों एवं स्वयंसेवकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

ऑपरेशन प्रहार' में ड्रग माफिया पर गाजियाबाद पुलिस का वार, 13 लाख कैश के साथ तस्कर गिरफ्तार

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। दिल्ली-एनसीआर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। ह्वऑपरेशन प्रहारह्व के तहत स्वाट टीम, अपराध शाखा और थाना विजयनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी कौस्तुभ उर्फ कार्तिक को सेक्टर-12, प्रताप विहार क्षेत्र से दबोचा। उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के अवैध मादक पदार्थों के अलावा 13 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बिहार से मादक पदार्थ लाकर गाजियाबाद और नोएडा में ऑनलाइन माध्यम से सप्लाई करता था। वह अपने साथियों के साथ स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के व्हाट्सऐप ग्रुपों में जुड़कर छात्रों को नशीले पदार्थों का प्रचार करता और ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए उनकी सप्लाई करता था। संयुक्त पुलिस टीम ने 4 अगस्त को संतोष मेडिकल सर्विस रोड, सेक्टर-12 प्रताप विहार के पास कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान ओजी गांजा, शिलॉन्ग गांजा, मैंगो गांजा और कोकीन समेत विभिन्न अवैध मादक पदार्थ तथा 13 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई।

इंदिरापुरम की ग्रीन बेल्ट पर चला प्रशासन का चाबुक, अवैध झुग्गियों पर कार्रवाई

100 फुटा रोड पर 3 संस्थान सील, तीन गांवों में सीमांकन; झुग्गियां नहीं हटीं तो चलेगा बुलडोजर

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। इंदिरापुरम में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है।100 फुटा रोड पर अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान अवैध गतिविधियां और अतिक्रमण मिलने पर तीन संस्थानों को सील कर दिया गया। संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद GDA सचिव को पत्र भेजकर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद GDA, नगर निगम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने कनावनी, प्रहलादगढ़ी और मकनपुर की सीमाओं का चिन्हीकरण कराया। टीम ने ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से बसाई गई झुग्गियों को हटाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया।

बिल्डर को एक दिन की मोहलत

नगर निगम की ग्रीन बेल्ट पर वर्ल्ड रेजिडेंसी बिल्डर द्वारा बसाई गई झुग्गियों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। झुग्गियां हटाने के लिए बिल्डर की ओर से एक दिन का समय मांगा गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में झुग्गियां नहीं हटाई गईं तो बुलडोजर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिना नक्शे का निर्माण तुरंत रुकेगा

ग्रीन बेल्ट पर बिना स्वीकृत नक्शे के हो रहे अनधिकृत निर्माण को लेकर GDA अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्माण पर तत्काल रोक लगाने को कहा गया है। कुछ अन्य संपत्तियों की जांच भी चल रही है।

गौशाला पर चला भूमाफियाओं का बुलडोजर! 150 लोगों पर तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप, दो गायों की मौत

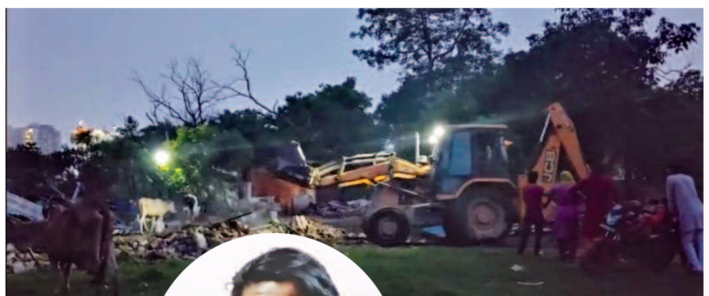

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। जिले में भूमाफियाओं के बढ़ते आतंक के बीच एक गौशाला को कथित रूप से जबरन हटाकर जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। गौशाला संचालक ने आरोप लगाया है कि करीब 150 लोगों ने बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी के गौशाला में पहुंचकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। इस दौरान दो गायों की मौत होने का भी दावा किया गया है। गौशाला संचालक सूरज पंडित के अनुसार, वह पिछले करीब सात वर्षों से उक्त जमीन पर गौशाला का संचालन कर रहे थे। गौशाला में लगभग 150 गायें थीं। उनका आरोप है कि गौशाला को हटाने के लिए इससे पहले भी दो बार आग लगाई जा चुकी है, जिसमें कई गायों की मौत हुई थी। इन घटनाओं को लेकर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। सूरज पंडित ने बताया कि एक बार फिर गौशाला को हटाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति में गौशाला को तोड़ना शुरू कर दिया। गौशाला में मौजूद लोगों के साथ कथित रूप से मारपीट की गई तथा पूरी गौशाला को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ के दौरान दो गायों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृत गायों को वहीं गड्ढा खोदकर दफना दिया गया।

लोनी में अवैध निर्माण पर जीडीए का चला बुलडोजर

गंगा विहार में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को किया ध्वस्त, विरोध के बीच जारी रही कार्रवाई

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण एवं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को लोनी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देशों के अनुपालन में प्रवर्तन जोन-03 की टीम ने गंगा विहार स्थित एक भूखंड पर स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार, 04 अगस्त 2026 को प्रभारी प्रवर्तन जोन-03 के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत भूखंड संख्या डी-4, गंगा विहार, लोनी, गाजियाबाद पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान यहां स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त निर्माण पाया गया था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय निर्माणकर्ता द्वारा इसका विरोध किया गया। हालांकि, मौके पर मौजूद प्राधिकरण पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया और इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखी गई। जीडीए की टीम ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निमार्णों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान प्रभारी प्रवर्तन जोन-08, संबंधित स्टाफ, प्राधिकरण पुलिस बल एवं प्रवर्तन दस्ता मौके पर मौजूद रहा।

कांवड़ मार्ग पर डीएम-एडिशनल पुलिस कमिश्नर की पैनी नजर, कंट्रोल रूम से सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

डासना से मुरादनगर और मेरठ तिराहे तक व्यवस्थाओं का निरीक्षण, कांवड़ियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ एवं एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरन नय्यर ने कांवड़ मार्ग डासना, मुरादनगर स्थित छोटा हरिद्वार तथा मेरठ तिराहा स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

अधिकारियों ने संबंधित विभागों को कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के सफल एवं सुरक्षित संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

कांवड़ियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मार्गों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जहां भी कोई कमी सामने आ रही है, उसका तत्काल निस्तारण कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कांवड़ मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सहायता, विश्राम स्थलों तथा सड़कों को गड्ढामुक्त रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि शिवभक्तों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कांवड़ियों से संवाद कर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया।

कांवड़ियों ने जनपद में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर संतोष जताते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। एक शिवभक्त ने कहा कि गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए 'ए-1' तैयारियां की गई हैं।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरन नय्यर ने कहा कि जनपद में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की सतत निगरानी है। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से कांवड़ मार्गों एवं प्रमुख स्थानों की गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा की अवधि तक सभी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।

कांवड़ शिविरों में गूंज रहे भजन-कीर्तन

हिंडन नदी के समीप स्थित कांवड़ सेवा शिविरों में शिवभक्त आध्यात्मिक माहौल के बीच भजन-कीर्तन का आनंद लेते हुए विश्राम करते नजर आए। शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, भोजन, विश्राम समेत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाना है।

गोकशी की साजिश पर पुलिस का शिकंजा, मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली

चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में अय्यूब घायल

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में गोकशी की घटना के बाद फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की मंगलवार को इंद्रापुरी चौकी क्षेत्र के कीकर वाले जंगल में बाइक सवार दो संदिग्धों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक, रोकने का प्रयास करने पर बाइक सवारों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त को लक्ष्मी गार्डन में गुल्फाम पुत्र वकील के घर पर गोकशी की घटना हुई थी। घटना में गुल्फाम समेत कई आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दोबारा गोकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर लोनी बॉर्डर पुलिस ने इंद्रापुरी चौकी क्षेत्र के कीकर वाले जंगल में चेकिंग अभियान शुरू किया। लालबाग की ओर जाने वाले रास्ते पर बाइक सवार दो लोगों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया।

घायल आरोपी की पहचान अय्यूब पुत्र जुम्मा निवासी इंद्रापुरी चौकी क्षेत्र के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

पूछताछ में अय्यूब के पिछली गोकशी की घटना में शामिल होने और दोबारा ऐसी वारदात की तैयारी किए जाने की जानकारी सामने आने की बात पुलिस ने कही है। पुलिस फरार साथी की तलाश में दबिश दे रही है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।

कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर लगाए फ्लेक्स

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को पुलिस उपायुक्त ग्रामीण श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी ने सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार, थाना प्रभारी अंकुर विहार, थाना प्रभारी ट्रोनिका सिटी, यातायात निरीक्षक एवं पुलिस बल के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया।

पुलिस टीम ने प्रतिबंधित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर जगह-जगह फ्लेक्स पोस्टर लगाकर वाहन चालकों एवं आमजन को मार्ग के संबंध में जागरूक किया। इसके साथ ही आसपास के कांवड़ यात्रा मार्ग का पैदल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग तथा यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कांवड़ियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुगम यातायात, प्रभावी भीड़ नियंत्रण और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

साथ ही संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतते हुए यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।

राजनगर एक्सटेंशन में महिला मनोचिकित्सक ने सातवीं मंजिल से कूदकर दी जान, मौके पर मौत

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित ऑफिसर सिटी-2 सोसाइटी में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। सोसाइटी के सातवीं मंजिल स्थित फ्लैट से कूदकर महिला मनोचिकित्सक डॉ. हमीका अग्रवाल ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतका के पिता गाजियाबाद के प्रसिद्ध मनोचिकित्सा डॉ. आर. चंद्रा ने बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले डॉ. हमीका का अपने पति से तलाक हो गया था। उनके अनुसार, तलाक के बाद वह मानसिक तनाव और अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रही थीं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

डासना जेल में बदली तस्वीर, दिव्यांग बंदियों को मिली नई उम्मीद

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। डासना जिला कारागार में दिव्यांग बंदियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में सराहनीय पहल की गई। जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार माँदड़ के निर्देशन में आयोजित विशेष जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम में दिव्यांग बंदियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ सहायक उपकरण वितरित किए गए।

कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद डॉ. सचिन वैश्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हापुड़, जेल अधीक्षक डासना श्री सीताराम शर्मा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री अंशुल चौहान सहित चिकित्सा विभाग एवं कारागार प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री अंशुल चौहान ने दिव्यांग बंदियों को दिव्यांग पेंशन, विवाह प्रोत्साहन, स्वरोजगार एवं पुनर्वास, दुकान-कियोस्क आवंटन सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कारागार से रिहाई के बाद पात्र दिव्यांगजन इन योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन की शुरूआत कर सकते हैं।

घुमंतू विकास बोर्ड के गठन से खुलेगा तरक्की का नया रास्ता

विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए ऐतिहासिक पहल, सीएम योगी का जताया आभार

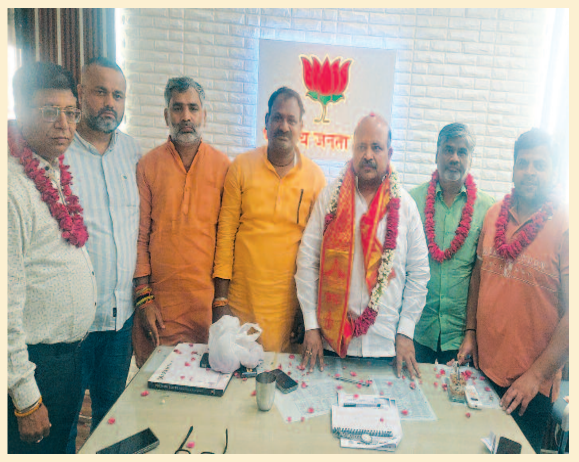

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दिए जाने पर महानगर गाजियाबाद में विमुक्त घुमंतू 12 जनजाति परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया।

परिषद के सदस्य धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल की मौजूदगी में प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। इस दौरान सदस्यों ने मुख्यमंत्री के निर्णय को घुमंतू एवं विमुक्त समुदायों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया।

महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने कहा कि बोर्ड के गठन से इन जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को नई दिशा मिलेगी। सरकार की योजनाओं के माध्यम से समुदाय के लोगों को भूमि के पट्टे, आवास, स्थायी कॉलोनियां, पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने का रास्ता आसान होगा।

उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। छात्रावासों एवं विशेष विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा के साथ आवास, भोजन और वर्दी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे घुमंतू एवं विमुक्त जनजातियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और भविष्य के अवसर मिल सकेंगे।

परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय को सम्मान, सुरक्षा और समग्र विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।

जनता दर्शन बना भरोसे का मंच, फरियादियों को मिल रहा त्वरित समाधान

डीएम बोले—अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक हर हाल में पहुंचे योजनाओं का लाभ

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। जनता दर्शन के माध्यम से आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान से शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है।

मंगलवार को मीडिया से संवाद करते हुए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिल सके।

जिले में 'गरीब का गृह प्रवेश', 'कब्जामुक्ति अभियान' और 'मिशन समर्थ' सहित विभिन्न अभियानों के जरिए जरूरतमंद, कमजोर, बेसहारा और वंचित लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राहत के साथ आत्मनिर्भर बनाने की पहल

डीएम ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य केवल लोगों को राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सक्षम बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के साथ ही कमजोर एवं वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। जनता दर्शन में पहुंचे लाभार्थियों ने कहा कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई होने से उन्हें राहत मिल रही है।

लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ के प्रति आभार जताया।

कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में करें सहयोग

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों और शिवभक्तों से कांवड़ यात्रा को सफल, सुरक्षित और ऐतिहासिक बनाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी समस्या की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दें, ताकि उसका शीघ्र निस्तारण कराया जा सके।

कांवड़ कंट्रोल रूम मुख्य 0120–2989508, मोदीनगर 01232–299210, गंगनहर 01232–299212, मेरठ तिराहा 0120–2989507, दुधेश्वरनाथ मंदिर 0120–2989506, टीलामोड़ 0120–2989509।

पुलिस : 07017652500

एनडीआरएफ : 09412221035, 0120–2766618